

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के वन कक्ष PF-400, 401, 409, 410, 413, 414 & 422 के रकबा 206.826 हे. वनभूमि में तानसी कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र.FP/ MP/ MIN/44238/2020

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-21/2023-FC दिनांक 08/08/2023

-0-

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा पत्र क्र./8-21/2023-FC दिनांक 08/08/2023 से 22 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई 22 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- i. The Ministry vide letter no. 11-164/2010-FC dated 25.03.2013 related to Forest and Environment Clearance to the coal mining project in PENCH Kanhan Coalfield located in Chhindwara District, Madhya Pradesh regarding Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine decided that after exhaustion of the underground reserve no further activity in the mine site, especially conversion to open cast should be allowed and regarding Tandsi-III Coal Mine decided that no mining activity may be allowed. The State Government shall provide its comments regarding present proposal keeping in view the said letter dated 25.03.2013 of the Ministry.
 - इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F-11-164/2010-FC Dated 25/03/2013 से तानसी खदान को कुछ शर्तों पर कोयला उत्खनन की स्वीकृति दी गई है स्वीकृत क्षेत्र में तानसी-1 एवं तानसी-2 कोयला ब्लॉक सम्मिलित है। एवं प्रस्तावित रकबा 206.826 हेक्टेयर वनभूमि तानसी-1 एवं तानसी-2 कोयला ब्लॉक के भीतर ही स्थित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक संस्था तानसी-3 कोयला ब्लॉक में किसी भी प्रकार का कोई कोयला उत्खनन का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/9779 दिनांक 07/11/2023 से कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति का अभिमत दिया गया है जो संलग्न है।
- ii. The Government of Madhya Pradesh vide their letter No. F-1/833/2022/10-11/3123 dated 13.07.2023 forwarded the proposal for diversion of 206.826 ha forest land for Tandsi under-ground coal mining project as a fresh diversion proposal without any reference to the renewal of the existing mine or diversion of forest area earlier, whereas, the DFO, Chhindwara (West) in his letter dated 15.06.2021 mentioned that an area of 299.44 ha was diverted earlier vide Ministry letter No. 8-145/86-FC dated 20.11.1991. The above variation needs clarification along with status of compliance of the stipulated conditions therein shall be submitted.
 - इस बिन्दु के सम्बन्ध में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पत्र क्र./104 दिनांक 26/10/2023 से प्रतिवेदित किया है कि रकबा 299.447 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित रकबा (542.557 हे. भूमि) का भाग है और यह वर्तमान प्रस्ताव उसी खदान सीमा में मिनरल्स कन्सेशन रूल्स 1960 के तहत लीज (1756.984 हे. भूमि) तथा सी.बी.ए. लीज (204.67 हे. भूमि) का भाग है।

- iii. The lease document submitted with the proposal pertains to the 3rd April 1976. The justification for submission of the proposal against the same at this belated stage needs submission. Moreover, the area mentioned in the lease document is 1756 ha. which indicates that either the instant proposal is not a standalone project, or the the lease document does not pertain to the instant proposal. A detailed justification in this regard shall be submitted.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत तानसी खदान रकबा 299.447 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित रकबा (542.557 हे. भूमि) भाग के कार्य में थी । अतः वर्तमान प्रस्ताव रकबा 206.826 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव समय पर प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्ताव परियोजना में स्टैडअलोन नहीं है शेष क्षेत्र के लिए प्रस्ताव वर्तमान प्रस्ताव के सफल समापन के बाद लागू किया जा सकता है।
- iv. The Conservator Forests Chindwara in his inspection report has mentioned that the area proposed for diversion is in seven patches and there is no clarity regarding the connectivity of the patches with each other. The justification in this regard is required to be submitted.
- प्रत्यावर्तन के लिये प्रस्तावित क्षेत्र सात खण्डों में है और खण्डों का एक-दूसरे से जुड़ाव गैरवनभूमि से है।
- v. It has been reported that the total 1961.654 ha land has been acquired under the MCR, 1980 & CB Act 1957 out of which 206.826 ha forest land has been proposed for diversion whereas as per the Villages wise breakup & Component wise breakup given in online Part-I, the details have given for total 373.16 ha land (Forest+ Non-Forest). The above variation needs clarification along with complete KML file of the Forest/Non-forest land involved in the project shall be submitted.
- इस तानसी खदान रकबा 299.447 हे. वनभूमि पर खनन कार्य के दौरान कोई धसाव रिकार्ड नहीं देखा गया है। एक धाऊनार्थ भूमिगत खदान, यह तानसी खदान के समीप है। दोनों खदानों का भूगर्भीय एकसमान है।
- vi. A detailed chronology indicating the history of mining lease and its renewals along with the detail of approvals accorded under FCA,1980 for the entire lease area shall be submitted.
- (1) इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खनि रियायत अधिनियम 1960 के तहत लीज रकबा 1756.984 हे. भूमि अधिग्रहित की गई थी तत्पश्चात् इसे भारत सरकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01/10/2021 से नवीनीकृत कर लीज अवधि को 31/03/2030 तक विस्तारित कर दिया गया है। भारत सरकार का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01/10/2021 की (प्रतिलिपि अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।)
 - (2) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-145/86-FC दिनांक 20/11/1991 से तानसी खदान हेतु रकबा 299.447 हे. वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित की गई । (प्रतिलिपि अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।)

- (3) कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत रकबा 542.557 हेक्टेयर भूमि दिनांक 22/05/1996 को अधिग्रहित की गई है। प्रतिलिपि अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।
- (4) कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत रकबा 204.67 हेक्टेयर भूमि दिनांक 18/03/2016 को अधिग्रहित की गई। (प्रति अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।)
- vii. As per the component wise breakup, the entire area including forest and non-forest land has been proposed for mining only. The State shall submit the details as to where the other ancillary activities like mineral processing, transportation, coal handling, infrastructure etc will be located.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोयला परिवहन, कोल हेण्डलिंग, निर्माण कार्य गैरवनभूमि पर किया गया है।
- viii. The status of Mine lease validity for the earlier approved 299.44 ha forest land shall be examined by the State Govt. and shall submit the present status of earlier approved forest land.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई भूमि की वैधता खदान के जीवन काल तक रहती है।
- ix. Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State.
- यह एक भूमिगत खदान है इसलिये किसी रिक्लेमेशन मेजर प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- x. The Cost Benefit analysis is required to be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022.
- आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित कास्ट बेनिफिट एनालिसिस पत्रक अनुलग्नक-5 पर संलग्न प्रस्तुत है।
- xi. In the part-1 of the application form, against the copy of approval of the mining plan the User Agency has submitted a letter dated 23.05.2007 communicating the salient features observed during the presentation of the Mining plan. A copy of the approval of the mining shall therefore be submitted.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में माईनिंग प्लान अनुमोदित होने का पत्र अपलोड कर दिया गया है। प्रतिलिपि अनुलग्नक-6 पर संलग्न प्रस्तुत है।
- xii. The relevance of the Mining plan under consideration in the year 2007 has to be examined in view of the technological advancement in the subsequent years. The State Govt. shall examine the matter and submit a revised Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- xiii. 3D subsidence report has been submitted in respect of Dhau North UG mine. Therefore, 3D subsidence report for the instant project shall be uploaded/ submitted.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रकबा 299.447 हे. वनभूमि पर खनन कार्य के दौरान कोई धसाव रिकार्ड नहीं देखा गया

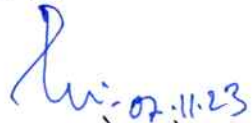
है। एक धाऊनार्थ भूमिगत खदान, इस तानसी खदान के समीप है। दोनों खदानों का भूगर्भीय स्थिति एकसमान है।

- xiv. The detail of safeguards proposed/ required in view of the location of the proposed area within a Tiger corridor shall be submitted.
- xv. इस बिन्दु के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/9779 दिनांक 07/11/2023 से कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति का अभिमत दिया गया है जो संलग्न है।
- xvi. The distance of proposed forest area from Satpura Tiger Reserve is 6.18 km. The area has a recorded presence of Tigers as elaborated in the SIR of DFO concerned. Therefore, the applicability of NBWL/ SBWL Clearance shall be examined and intimated by the CWLW along with his comments on the proposal.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/9779 दिनांक 07/11/2023 से कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति का अभिमत दिया गया है जो संलग्न है।
- xvii. The details of coal evacuation plan and involvement of forest land, if any, shall be intimated.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि coal evacuation plan में किसी प्रकार की कोई वनभूमि नहीं आती है। यह कार्य गैरवनभूमि में किया जावेगा।
- xviii. The State Govt. recommended the proposal subject to a study which is to be carried out by the WII, Dehradun and the State Forest Research Institute, Jabalpur to curb the noise level arises due to mining and allied activities. However, the copy of undertaking from the user agency to bear the cost of study has not been submitted. The same needs submission.
- इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अनुलग्नक- 7 पर संलग्न प्रस्तुत है।
- xix. The component wise/ purpose wise KML file/Shape file of the 299.44 ha already diverted forest land shall be submitted.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा रकबा 299.447 हेक्टेयर वनभूमि की KML File ऑनलाईन के भाग-1 के अनुक्रमांक-M-2 (vii) में अपलोड की गई जिसे हरे रंग में दर्शाया गया है।
- xx. Calculated area of Mining lease boundary through KML file is found 373.183 ha instead of 1318.283 ha as per the Mining plan whereas the State Govt. reported total area involved in the project is 1961.654 ha, further the lease document submitted mentions the area as 1756 ha. This variation needs clarification along with the KML file.
- इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा खनि रियायत अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई रकबा 1756.984 हेक्टेयर क्षेत्र की KML file. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के M-2 (vii) में अपलोड की गई है जिसे नारंगी रंग से दर्शाया गया है। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित रकबा 542.557 हे. भूमि क्षेत्र की KML file. भी इसी M-2 (vii) में अपलोड की गई है जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है तथा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित रकबा 204.67 हे. भूमि क्षेत्र की KML file. भी इसी M-2 (vii) में अपलोड की गई है जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है।

- xxi. Out of 373.183 ha Mining lease KML file uploaded on PARIVESH, total area of forest land present in the Mining lease is found 219.852 ha whereas the user agency has only applied for diversion of 206.826 ha. This needs clarification.
- आवेदक संस्था द्वारा रकबा 219.852 हे. के स्थान पर रकबा 206.826 हेक्टेयर की KML file. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के अनुक्रमांक C- (ii)(a) में 7 पेंचस में अपलोड की गई है जिसे हरें रंग से दर्शाया गया है ।
- xxii. High resolution satellite imagery shows the presence of Road, River (Tambiya Nadi) and plantation work in the forest land proposed for diversion. This needs clarification.
- आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि यह प्रस्ताव भूमिगत उत्खनन कार्य हेतु प्रस्तावित है इसलिये उपरी तल सतह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा
- xxiii. Tambiya River and its tributary are flowing through the forest land proposed for diversion. In this regard the comments of the Water Resource Department of the State/State Government on the effect of underground mining on ground water recharge and existing water tank and measures to protect river subsidence due to under-ground mining shall be submitted. The details of study carried out, if any in this regard shall also be submitted.
- आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि जल संसाधन विभाग भोपाल को इस टिप्पणी हेतु पत्र लिखा गया है। पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक-8 पर संलग्न प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कोल मार्ईन्स रेगूलेशन 2017 अण्डर मार्ईन्स एक्ट 1952 के तहत महानिदेशक, खान सुरक्षा भारत सरकार द्वारा दिये गये नियमों एवं शर्तों के अनुसार भूमिगत उत्खनन कार्य किया जाता है ।

अतः वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक/1453 दिनांक 06/11/2023 से प्राप्त जानकारी आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 07/11/2023

पृ. क्रमांक/एफ-1/833/2023/10-11/4973
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश ।
- 2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- 3 महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र पोस्ट डुंगरिया तहसील जामुई जिला छिन्दवाड़ा म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक/मा.चि./ 1453
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक 6-11-2023

✓ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(कक्ष भू-प्रबंध)
वन भवन
म0प्र0 भोपाल

विषय:- तानसी कोल परियोजना हेतु 206.826 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(प्रकरण क्रमांक / FP/MP/MIN/44238/2020)

- संदर्भ:-
1. आपका पत्र क्रमांक 4343 दिनांक 29.09.2023
 2. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 2075 दिनांक 27.10.2023
 3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1435 दिनांक 30.10.2023 एवं
 4. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 3020 दिनांक 4.11.2023

—000—

निवेदन है कि विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से प्रकरण में चाहे गये 22 बिंदुओं की जानकारी वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल के पत्र क्रमांक 2075 दिनांक 27.10.2023 से प्राप्त कर इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1435 दिनांक 30.10.2023 से प्रेषित की गयी थी।

संदर्भित पत्र क्रमांक 4 से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल द्वारा प्रकरण में 22 बिंदुओं की संशोधित जानकारी भेजी है, जो की आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र :- उरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त
06/11/23

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1454

छिंदवाड़ा, दिनांक 6-11-2023

प्रतिलिपि:- वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त
06/11/23

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2023/ 3020
प्रति.

छिन्दवाड़ा दिनांक 04.11.23

वन संरक्षक
छिन्दवाड़ा वन वृत्त
छिन्दवाड़ा

संशोधित

विषय :- तानसी कोल परियोजना हेतु 206.826 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/MIN/44238/2020)

संदर्भ :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन के पत्र क्रमांक /एफ-1/833/2022/10-11/4342 दिनांक 29.09.2023
2. वे०को०फी०लिमि० कन्हान क्षेत्र डुंगरिया के पत्र क्रमांक 104 दिनांक 26.10.2023

- संक्षेप -

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत दमुआ वन परिक्षेत्र के रकबा 206.826 हे० वनभूमि की तानसी भूमिगत खदान हेतु प्रकरण प्रस्ताव क्रमांक /FP/MP/MIN/37580/2018 से ऑनलाईन किया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से चाही गई विदुवार जानकारी वे०को०फी०लिमि० कन्हान क्षेत्र डुंगरिया से प्राप्त कर निम्नानुसार है।

S.No.	Query	Compliance
1	The Ministry vide letter no. 11-164/2010-FC dated 25.03.2013 related to Forest and Environment Clearance to the coal mining project inPench Kanhan Coalfield located in Chhindwara District, Madhya Pradesh regarding Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine decided that after exhaustion of the underground reserve no further activity in the mine site, especially conversion to open cast should be allowed and regarding <i>Tandsi-III Coal Mine decided that no mining activity may be allowed.</i> The State Government shall provide its comments regarding present proposal keeping in view the said letter dated 25.03.2013 of the Ministry.	As per letter no. 11-164/2010-FC dated 25.03.2013 Tandsi Mine have permission to operate underground mining which extends within Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine block . And above applied application of 206.826 Ha is lying in boundary of Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine block. In addition, it is to specify that it is no operation has been carried out in Tandsi-III coal block.
2	The Government of Madhya Pradesh vide their letter No. F-1/833/2022/10-11/3123 dated 13.07.2023 forwarded the proposal for diversion of 206.826 ha forest land for Tandsi under-ground coal mining project as a fresh diversion proposal without any reference to the renewal of the existing mine or diversion of forest area earlier, whereas, the DFO, Chhindwara (West) in his letter dated 15.06.2021 mentioned that an area of 299.44 ha was diverted earlier vide Ministry letter No. 8-145/86-FC dated 20.11.1991. The above variation needs clarification	The 299.447 ha diverted FC land is under part of CBA(542.557ha) & this current proposal is part of MCR lease (1756.984 ha) & CBA lease (204.67 ha) in the same mine boundary.

	along with status of compliance of the stipulated conditions therein shall be submitted.	
3	The lease document submitted with the proposal pertains to the 3rd April 1976. The justification for submission of the proposal against the same at this belated stage needs submission. Moreover, the area mentioned in the lease document is 1756 ha. which indicates that either the instant proposal is not a standalone project, or the lease document does not pertain to the instant proposal. A detailed justification in this regard shall be submitted.	Earlier approved 299.447 ha FC land under CBA lease was in operation. Hence current proposal (206.826 Ha) was applied timely. Yes, this proposal is not standalone in project, proposal for remaining area can be applied after successful completion of the Current proposal.
4	The Conservator Forests, Chhindwara in his inspection report has mentioned that the area proposed for diversion is in seven patches and there is no clarity regarding the connectivity of the patches with each other. The justification in this regard is required to be submitted.	Area proposed for diversion is in seven patches and the connectivity of the patches with each other is by non forest land.
5	It has been reported that the total 1961.654 ha land has been acquired under the MCR, 1980 & CB Act 1957 out of which 206.826 ha forest land has been proposed for diversion whereas as per the Villages wise breakup & Component wise breakup given in online Part-I, the details have given for total 373.16 ha land (Forest+ Non-Forest). The above variation needs clarification along with complete KML file of the Forest/Non-forest land involved in the project shall be submitted.	The details have been given for total 373.16 ha land (Forest + Non-Forest), of which the 206.826 ha land comes under forest land and 166.334 ha land is non forest land . Out of 1961 ha (MCR 1756.984 +CBA 204.67) only 817 Ha area fall in the Mine Boundary. Tandsi Mine proposed in this proposal only 373.16 ha. KML file is enclosed.
6	A detailed chronology indicating the history of mining lease and its renewals along with the detail of approvals accorded under FCA, 1980 for the entire lease area shall be submitted.	The MCR lease 1756.984 Ha was acquired as on dated 3rd April 1976. Then after it was renewed on dated 01.10.2021 valid upto 31-03-2030. Copy of Gazette Notification date 01-01-2021 enclosed Annexure-1. Forest land 299.447 Ha Land was diverted as on 20.11.1991 vide letter no 8-145/86-FC. As annexure-2. CBA land 542.557 HA was acquired as on 22.05.1999. As annexure-3. CBA land 204.67 ha was acquired as on 18.03.2016. As annexure-4.
7	As per the component wise breakup, the entire area including forest and non-forest land has been proposed for mining only. The State shall submit the details as to where the other ancillary activities like mineral processing, transportation, coal handling, infrastructure etc will be located.	Ancillary activities like mineral processing, transportation, coal handling, infrastructure etc. will be located in non forest area.
8	The status of Mine lease validity for the earlier approved 299.44 ha forest land shall be examined by the State Govt. and shall submit the present status of earlier approved forest land.	Earlier approved mining lease validity is under CBA with unlimited validity period/life period of mine/ till exhaustion of resource.
9	Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State.	This is an Underground Mine; Hence no reclamation measure is required.

10	The Cost Benefit analysis is required to be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022.	Revised cost benefit analysis is enclosed. As annexure-5.
11	In the part-1 of the application form, against the copy of approval of the mining plan the User Agency has submitted a letter dated 23.05.2007 communicating the salient features observed during the presentation of the Mining plan. A copy of the approval of the mining shall therefore be submitted.	Approval copy of Mining Plan is enclosed. As annexure-6.
12	The relevance of the Mining plan under consideration in the year 2007 has to be examined in view of the technological advancement in the subsequent years. The State Govt. shall examine the matter and submit a revised Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.	There is no change in technology .
13	3D subsidence report has been submitted in respect of Dhau North UG min, therefore 3D subsidence report for the instant project shall be uploaded/ submitted.	No subsidence record is observed during the mining operation on the 299.447 Ha land. And Dhau North UG is in nearby the Tandsi Mine. The geology of the both Mine are Similar.
14	The detail of safeguards proposed/ required in view of the location of the proposed area within a Tiger corridor shall be submitted.	The proposal is for the underground mining of the coal hence there would not be any direct impact of the mining on the wildlife. But due to transportation of the coal there would be some disturbance to wildlife crossing the roads through which the coal would be transported, hence the speed breakers should be installed on the roads through which the coal would be transported, signages of wildlife crossing should also be installed. The user agency can positively contribute by creating waterholes for wildlife with the help of the forest departments inside the forest area.
15	The distance of proposed forest area from Satpura Tiger Reserve is 6.18 km. The area has a recorded presence of Tigers as elaborated in the SIR of DFO concerned. Therefore, the applicability of NBWL/ SBWL Clearance shall be examined and intimated by the CWLW along with his comments on the proposal.	May kindly be replied by forest Headquarter.
16	The details of coal evacuation plan and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	No forest land is involved in the coal Evacuation plan.
17	The State Govt. recommended the proposal subject to a study which is to be carried out by the WII, Dehradun and the State Forest Research Institute, Jabalpur to curb the noise level arises due to mining and allied activities. However, the copy of undertaking from the user agency to bear the cost of study has not been submitted. The same needs submission.	Undertaking for bearing the cost of study is submitted. Enclosed as Annexure - 7.
18	The component wise/ purpose wise KML file/Shape file of the 299.44 ha already diverted forest land shall be submitted.	Total diverted FC land 299.447 Ha KML file is uploaded.

19	Calculated area of Mining lease boundary through KML file is found 373.183 ha instead of 1318.283 ha as per the Mining plan whereas the State Govt. reported total area involved in the project is 1961.654 ha, further the lease document submitted mentions the area as 1756 ha. This variation needs clarification along with the KML file.	As asked, the KML file depicting the details of 1756 Ha. land (MCR lease), 542.557 Ha land (CBA), 204.67 Ha land (CBA) is prepared and enclosed. The MCR lease 1756.984 Ha was acquired as on dated 3rd April 1976. Then after it was renewed on dated 01.10.2021 valid upto 31-03-2030. Copy of Gazette Notification date 01-01-2021 enclosed Annexure-1. Forest land 299.447 Ha Land was diverted as on 20.11.1991 vide letter no 8-145/86-FC. As annexure-2. CBA land 542.557 HA was acquired as on 22.05.1999. As annexure-3. CBA land 204.67 ha was acquired as on 18.03.2016. As annexure-4.
20	Out of 373.183 ha Mining lease KML file uploaded on PARIVESH, total area of forest land present in the Mining lease is found 219.852 ha whereas the user agency has only applied for diversion of 206.826 ha. This needs clarification.	Revised KML file is uploaded.
21	High resolution satellite imagery shows the presence of Road, River (Tambiya Nadi) and plantation work in the forest land proposed for diversion. This needs clarification.	In Year 2022-21 mixed plantation works done in Compartment no 409 area 50 hac and compartment no 414 area 25 hac. The current proposal is for underground mining only, which will have no impact on the forestry/ surface features of the area And in Year 2020-21
22	Tambiya River and its tributary are flowing through the forest land proposed for diversion. In this regard the comments of the Water Resource Department of the State/State Government on the effect of underground mining on ground water recharge and existing water tank and measures to protect river subsidence due to under-ground mining shall be submitted. The details of study carried out, if any in this regard shall also be submitted.	The request for comment has been submitted to the Water Resource Department of State. A copy of the application made to Principal/Chief Engineer (Water Resourced Department), Bhopal. As annexure - 8. Further, underground working will be done as per the condition of permissions which is imposed by Director General of Mine Safety, for the working below river/water bodies under Coal Mines Regulations-2017 under Mines Act 1952.

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2023/ 3021

प्रतिलिपि :- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित। सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

(2) महाप्रबंधक वे0को0फी0लिमि0 कन्हाज क्षेत्र दुंगरिया की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा. दिनांक/04.11.23

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा



वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड/Western Coalfields Limited

मिनिरल कम्पनी(A Miniratna Company)
कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी(A Subsidiary of Coal India Limited)
CIN-U10100MH1975GO1018626



क्षेत्रीय महाप्रबन्धक का कार्यालय, कन्हान क्षेत्र
पता: वे.को.लि., कन्हान क्षेत्र, पो: दुर्गाया, जिला: छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश, पिन:480553
Email: agmkanhan@westerncoal.gov.in

Office of Area General Manager, Kanhan Area
Address: WCL, Kanhan Area, PO: Dungaria, Dist: Chhindwara, MP, PIN:480553
Phone: 07160-231064

संदर्भ सं- वेकोलि/कन्हान/क्षे.म.प्र./2023-24/104

दिनांक: 26-10-2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

पश्चिम (सा.) वनमण्डल, छिन्दवाड़ा।

विषय: वनमण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के वन कक्ष PF-400, 401, 409, 410, 413, 414 & 422 के रकबा 206.826 हे. वनभूमि में तानसी कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44238/2020

सदर्भ संख्या: क्रमांक/मा.चि./2872, दिनांक 18-10-2023

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुसार, चाही गई जानकारी तालिकाभुसार, निम्न है:-

S.No.	Query	Compliance
1	The Ministry vide letter no. 11-164/2010-FC dated 25.03.2013 related to Forest and Environment Clearance to the coal mining project in Pench Kanhan Coalfield located in Chhindwara District, Madhya Pradesh regarding Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine decided that after exhaustion of the underground reserve no further activity in the mine site, especially conversion to open cast should be allowed and regarding Tandsi-III Coal Mine decided that no mining activity may be allowed. The State Government shall provide its comments regarding present proposal keeping in view the said letter dated 25.03.2013 of the Ministry.	As per letter no. 11-164/2010-FC dated 25.03.2013 Tandsi Mine have permission to operate underground mining which extends within Tandsi- I & Tandsi-II Coal Mine block . And above applied application of 206.826 Ha is lying in boundary of Tandsi- I& Tandsi-II Coal Mine block. In addition, it is to specify that it is no operation has been carried out in Tandsi-III coal block.



[Handwritten Signature]

SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

2	<p>The Government of Madhya Pradesh vide their letter No.F-1/833/2022/10-11/3123 dated 13.07.2023 forwarded the proposal for diversion of 206.826 ha forest land for Tandsi under-ground coal mining project as a fresh diversion proposal without any reference to the renewal of the existing mine or diversion of forest area earlier, whereas, the DFO, Chhindwara (West) in his letter dated 15.06.2021 mentioned that an area of 299.44 ha was diverted earlier vide Ministry letter No. 8-145/86-FC dated 20.11.1991. The above variation needs clarification along with status of compliance of the stipulated conditions therein shall be submitted</p>	<p>The 299.447 ha diverted FC land is under part of CBA(542.557ha) & this current proposal is part of MCR lease (1756.984 ha) & CBA lease(204.67 ha) in the same mine boundary.</p>
3	<p>The lease document submitted with the proposal pertains to the 3rd April 1976. The justification for submission of the proposal against the same at this belated stage needs submission. Moreover, the area mentioned in the lease document is 1756 ha. which indicates that either the instant proposal is not a standalone project, or the lease document does not pertain to the instant proposal. A detailed justification in this regard shall be submitted.</p>	<p>Earlier approved 299.447 ha FC land under CBA lease was in operation. Hence current proposal (206.826 Ha) was applied timely. Yes, this proposal is not standalone in project, proposal for remaining area can be applied after successful completion of the Current proposal.</p>
4	<p>The Conservator Forests, Chhindwara in his inspection report has mentioned that the area proposed for diversion is in seven patches and there is no clarity regarding the connectivity of the patches with each other. The justification in this regard is required to be submitted.</p>	<p>Area proposed for diversion is in seven patches and the connectivity of the patches with each other is by non forest land.</p>
5	<p>It has been reported that the total 1961.654 ha land has been acquired under the MCR, 1980 & CB Act 1957 out of which 206.826 ha forest land has been proposed for diversion whereas as per the Villages wise breakup & Component wise breakup given in online Part-I, the details have given for total 373.16 ha land (Forest+ Non-Forest). The above variation needs clarification along with complete KML file of the Forest/Non-forest land involved in the project shall be submitted.</p>	<p>The details have been given for total 373.16ha land (Forest + Non-Forest), of which the 206.826 ha land comes under forest land and 166.334 ha land is non forest land . Out of 1961 ha (MCR 1756.984 +CBA 204.67) only 817 Ha area fall in the Mine Boundary. Tandsi Mine proposed in this proposal only 373.16 ha. KML file is enclosed.</p>

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

6	A detailed chronology indicating the history of mining lease and its renewals along with the detail of approvals accorded under FCA, 1980 for the entire lease area shall be submitted.	(1) The MCR lease 1756.984 Ha was acquired as on dated 3rd April 1976. Then after it was renewed on dated 01.10.2021 valid upto 31-03-2030. Copy of Gazette Notification date 01-01-2021 enclosed Annexure-1. (2) Forest land 299.447 Ha Land was diverted as on 20.11.1991 vide letter no 8-145/86-FC. As annexure-2. (3) CBA land 542.557 HA was acquired as on 22.05.1999. As annexure-3. (4) CBA land 204.67 ha was acquired as on 18.03.2016. As annexure-4.
7	As per the component wise breakup, the entire area including forest and non-forest land has been proposed for mining only. The State shall submit the details as to where the other ancillary activities like mineral processing, transportation, coal handling, infrastructure etc will be located.	Ancillary activities like mineral processing, transportation, coal handling, infrastructure etc. will be located in non forest area.
8	The status of Mine lease validity for the earlier approved 299.44 ha forest land shall be examined by the State Govt. and shall submit the present status of earlier approved forest land.	Earlier approved mining lease validity is under CBA with unlimited validity period/life period of mine/ till exhaustion of resource.
9	Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State.	This is an Underground Mine; Hence no reclamation measure is required.
10	The Cost Benefit analysis is required to be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022.	Revised cost benefit analysis is enclosed. As annexure-5.
11	In the part-1 of the application form, against the copy of approval of the mining plan the User Agency has submitted a letter dated 23.05.2007 communicating the salient features observed during the presentation of the Mining plan. A copy of the approval of the mining shall therefore be submitted.	Approval copy of Mining Plan is enclosed. As annexure-6.

[Handwritten Signature]
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

[Handwritten Signature]

12	The relevance of the Mining plan under consideration in the year 2007 has to be examined in view of the technological advancement in the subsequent years. The State Govt. shall examine the matter and submit a revised Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.	There is no change in technology .
13	3D subsidence report has been submitted in respect of Dhau North UG min, therefore 3D subsidence report for the instant project shall be uploaded/ submitted.	No subsidence record is observed during the mining operation on the 299.447 Ha land. And Dhau North UG is in nearby the Tandsi Mine. The geology of the both Mine are Similar.
14	The detail of safeguards proposed/ required in view of the location of the proposed area within a Tiger corridor shall be submitted.	As proposed diverted area is in Underground Mine no safeguard is required.
15	The distance of proposed forest area from Satpura Tiger Reserve is 6.18 km. The area has a recorded presence of Tigers as elaborated in the SIR of DFO concerned. Therefore, the applicability of NBWL/ SBWL Clearance shall be examined and intimated by the CWLW along with his comments on the proposal.	May kindly be replied by forest department.
16	The details of coal evacuation plan and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	No forest land is involved in the coal Evacuation plan.
17	The State Govt. recommended the proposal subject to a study which is to be carried out by the WII, Dehradun and the State Forest Research Institute, Jabalpur to curb the noise level arises due to mining and allied activities. However, the copy of undertaking from the user agency to bear the cost of study has not been submitted. This same needs submission.	Undertaking for bearing the cost of study is submitted. Enclosed as Annexure - 7.
18	The component wise/ purpose wise KML file/Shape file of the 299.44 ha already diverted forest land shall be submitted.	Total diverted FC land 299.447 Ha KML file is uploaded.

[Handwritten signature]

SUB AREA V.C.
TANDSI SUB AREA

[Handwritten signature]

19	Calculated area of Mining lease boundary through KML file is found 373.183 ha instead of 1318.283 ha as per the Mining plan whereas the State Govt. reported total area involved in the project is 1961.654 ha, further the lease document submitted mentions the area as 1756 ha. This variation needs clarification along with the KML file.	As asked, the KML file depicting the details of 1756 Ha. land (MCR lease), 542.557 Ha land (CBA), 204.67 Ha land (CBA) is prepared and enclosed. (1)The MCR lease 1756.984 Ha was acquired as on dated 3rd April 1976. Then after it was renewed on dated 01.10.2021 valid upto 31-03-2030. Copy of Gazette Notification date 01-01-2021 enclosed Annexure-1. (2)Forest land 299.447 Ha Land was diverted as on 20.11.1991 vide letter no 8-145/86-FC. As annexure-2. (3)CBA land 542.557 HA was acquired as on 22.05.1999. As annexure-3. (4)CBA land 204.67 ha was acquired as on 18.03.2016. As annexure-4.
20	Out of 373.183 ha Mining lease KML file uploaded on PARIVESH, total area of forest land present in the Mining lease is found 219.852 ha whereas the user agency has only applied for diversion of 206.826 ha. This needs clarification.	Revised KML file is uploaded.
21	High resolution satellite imagery shows the presence of Road, River (Tambiya Nadi) and plantation work in the forest land proposed for diversion. This needs clarification.	The current proposal is for underground mining only, which will have no impact on the forestry/ surface features of the area.
22	Tambiya River and its tributary are flowing through the forest land proposed for diversion. In this regard the comments of the Water Resource Department of the State/State Government on the effect of underground mining on ground water recharge and existing water tank and measures to protect river subsidence due to under-ground mining shall be submitted. The details of study carried out, if any in this regard shall also be submitted.	The request for comment has been submitted to the Water Resource Department of State. A copy of the application made to Principal/Chief Engineer (Water Resourced Department), Bhopal. As annexure - 8. Further, underground working will be done as per the condition of permissions which is imposed by Director General of Mine Safety, for the working below river/water bodies under Coal Mines Regulations-2017 under Mines Act 1952.

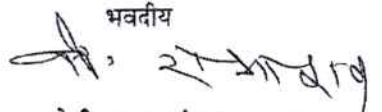
उपरोक्त जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित है।

धन्यवाद।

संलग्न:- यथोपरि।

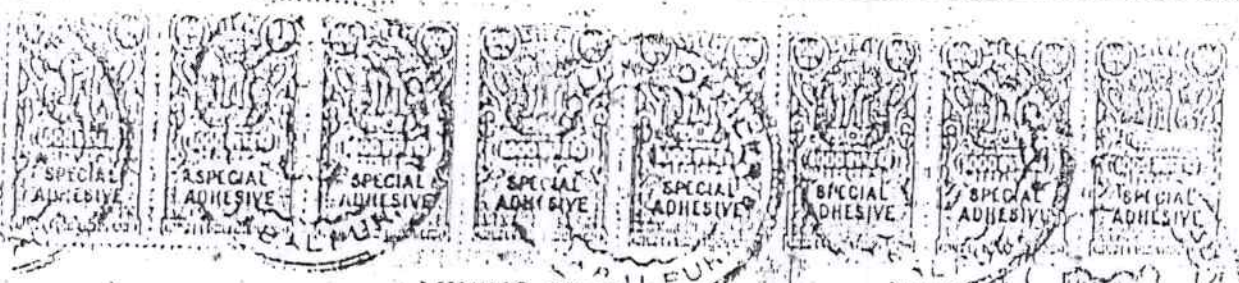
प्रतिलिपि

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन-संरक्षक (भू-प्रबंध), वनविभाग, भोपाल।
2. मुख्य वनसंरक्षक, छिन्दवाड़ा वन-वृत्त, छिन्दवाड़ा।
3. महाप्रबंधक (भू/राजस्व), वेकोलि मुख्यालय, नागपुर।
4. महाप्रबंधक (पर्यावरण), वेकोलि मुख्यालय, नागपुर।
5. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, ज्ञानसी उपक्षेत्र।
6. क्षेत्रीय योजना अधिकारी, कन्हान क्षेत्र।
7. कार्यालय प्रति।

भवदीय

 क्षेत्रीय महाप्रबंधक
 कन्हान क्षेत्र 25.10.17
 23



SUB AREA PROJECT
 TANDSI SUB AREA



MINING LEASE

(see Rule 31 of the Mineral Concession Rules, 1960)

THIS INDENTURE made this day 23 day of April 1976 between the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "State Government" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the one part and _____ (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns) _____ (Name of person with address and occupation) and _____ (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as "the lessees", which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns). _____ (Name and address of partners) son of _____ of _____ son of _____ of _____ son of _____ of _____ all carrying on business in partnership under the firm name and style of _____ (name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932, (IX of 1932) and having their registered office at _____ in the town of _____ (hereinafter referred to as "the lessee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns). Coal India Ltd; (Ex- Coal Mines Authority Ltd); (Name of company) a company registered under Indian Companies Act under which incorporated) and having its registered office at 10, Netaji Subhas Road, CALCUTTA, (Address) (hereinafter referred to as the lessee which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS the lessee/lessees has/have applied to the State Government in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said Rules) for a mining lease for COAL in respect of the lands described in Part I of the Schedule hereunder written and has/have deposited with the State Government the sum Rs. 1000/- as security and the sum of Rs. 500/- for meeting the preliminary expenses for a mining lease and whereas the lessee is in possession of a valid certificate of approval and Income-Tax Clearance Certificate (and WHEREAS the Central Government has approved the grant of lease).*



*In case of minerals included in Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation & Devt) Act, 1957.

WITNESSETH that in consideration of the rents and royalties covenants and agreements by and in these presents and the schedule hereunder written reserved and contained and on the part of the lessee/lessees to be paid, observed and performed, the State Government (with the approval of the Central Government)* hereby grants and demises unto lessee/lessees.

All those (the mines beds/veins seams of COAL) there state (the mineral or minerals) (hereinafter and in the Schedule referred to as the said mineral) situated lying and being in or under the lands which are referred to in Part I of the said schedule, together with the liberties, powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection here with which are mentioned in Part II of the said Schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties, powers and privileges which are mentioned in Part III of the said Schedule EXCEPT and reserving out of this demise unto the State Government the liberties, powers and privileges mentioned in Part IV of the said Schedule TO HOLD the premises hereby granted and demised unto the lessee/lessees from the 1ST (First) day APRIL 1974. for the term of 30 (Thirty) years thence next ensuing YIELDING AND PAYING therefore unto the State Government the several rents and royalties mentioned in Part V of the said Schedule at the respective times therein specified subject to the provisions contained in Part VI of the said Schedule and the lessee/lessees hereby covenants/covenant with the State Government as in Part VII of the said Schedule is expressed and the State Government hereby covenants with the lessee/lessees as in Part VIII of the said Schedule as expressed AND it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in Part IX of the said Schedule is expressed.

IN WITNESS WHEREOF these presents* have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to as shown on the plans annexed.

REP
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

PART I
The Area of this Lease

Ranpur, Kusum Pather & village

Location and area of the lease.

All that tract of lands situated at Jhuraimou, Tansi, Kangra, Lakhur (Description of area or areas) 43:1.57 acres Or in (Pargana) in 1756/984 Hectares. the Registration District of Chhindwara Sub District Chhindwara and Thana Dampu bearing Cadastral Survey Nos. as shown on the plans attached.

*In case of minerals specified in Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation and Leasing) Act, 1957.

74-2

V. K. MACHHARJUN
B.Sc. (Mining) AGM (M)
Mining Consultant / ROP

area of 4541.57 acres OR 1756.904 hectares or thereabouts delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured Red and bounded as follows:-

- On the North by Part of villages Tansi, Khuraiam & Kusumpat
 - On the South by Part of villages Kangra and Ranpur.
 - On the East by Part of villages Kangra, Chandania, Lakhpur & Kiraimau and
 - On the West by Part of unsurveyed villages Kusumpat & Hantharak
- hereinafter referred to as "the said lands".

PART II

Liberties, Powers and Privileges to be exercised and enjoyed by the Lessee/Lesseees subject to the Restrictions and Conditions in Part III.

1. Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to search for mine bore dig drill for win work dress process convert carry away and dispose of the said mineral/minerals. To enter upon land and search for win work etc.
2. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to sink drive make maintain and use in the said lands and pits shaft inclines drifts levels waterways, airways and other works (and to use maintain deepen or extend any existing works of the like nature in the said lands). To sink and make pits shafts and inclines etc.
3. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or under the said lands any engines machinery plant dressing floors furnaces coke ovens bricks-kilns workshops store-houses bungalows godowns sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands. To bring and use machinery equipment etc.
4. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, railways, roads, airfields landing grounds and other ways in or over the said lands and to use maintain and go and repass with or without horses cattle wagons aircrafts locomotives or other vehicles over the same (or any existing tramways, railways, roads and other ways in or over the said lands) on such conditions as may be agreed to. To make roads & ways etc. & use existing roads & ways
5. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to quarry and get stone gravel and other building and road materials and clay and to use and employ the same and to manufacture such clay into bricks or tile and to use such bricks or tiles but not to sell any such material bricks or tiles. To get building & road materials etc.
6. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part but subject to the rights of any existing or future lesseees and with the written permission of Deputy Commissioner/Collector to appropriate and use water from any streams water courses, springs or other sources in or upon the said lands and to divert step up or dam any such stream or water-course and collect or impound any such water and to make construct and maintain any water course culverts drains or reservoirs but not as to deprive any cultivated lands, villages, buildings or watering places for livestock of a reasonable supply of water as before accustomed nor in any way. To use water from stream etc.

RQP
SUB AREA MANAGER
SUB AREA

75

V. K. MACHMARIAL
B.Sc. (Mining) AISM (Mining), F.C.M.
Mining Consultant / RQP

COLLECTOR,
CHHINDWARA

to foul or pollute any streams or springs. Provided that the lessee/lessees shall not interfere with the navigation in any navigable stream nor shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

To use land for stacking, heaping, depositing purposes.

7. Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of stacking, heaping, storing or depositing therein any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.

Beneficiation and conveying away of production.

8. (a) Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the said lands to beneficiate any ore produced from the said lands and to carry away such beneficiated ore.

To make coke (To be used in case of coal only).

(b) Liberty and power upon the said lands to convert into coke any coal or coal dust produced from the said lands and to carry away such coke.

To clear brushwood and to fell and utilise trees etc.

9. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part and subject to the existing rights of the others and save as provided in clause (3) of Part III of this Schedule to clear undergrowth and brushwood and to fell and utilise any trees or timber standing or found on the said lands provided that the State Government may ask the lessee/lessees to pay for any trees or timber felled and utilised, by him/them at the rates specified by the Deputy Commissioner/Collector or the State Government.

PART III

Restrictions and Conditions as to the exercise of the Liberties Powers and Privileges in Part II

No building etc. upon certain places.

1. No building or thing shall be erected set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground or place held sacred by any class of persons or any house or village site, public road or other place which the State Government may determine as public ground nor in such a manner as to injure or prejudicially affect any buildings, work, property or rights of other persons and no land shall be used for surface operations which is already occupied by persons or other than the State Government for works or purposes not included in this lease. The lessee/lessees shall not also interfere with any right of way, well or tank.

Permission for surface operations in a land not already in use.

2. Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessee/lessees shall give to Deputy Commissioner/Collector of the District two calendar months previous notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used if objection is issued by the Deputy Commissioner/Collector within two months after the receipt by him of such notice unless the objections so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived.

To cut trees in reserved lands.

3. The lessee/lessees shall not without the express sanction of the Deputy Commissioner/Collector cut down or injure any timber trees on the said lands but may without such sanction clear away any brushwood or undergrowth which interferes with any operations authorised by these presents. The Deputy Commissioner/Collector may also require the lessee/lessees to pay for any trees or timber cut down or injured by him/them at the rates specified by the Deputy Commissioner/Collector or the State Government.

RQP
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

75.A

V. K. NACHAR
S. Sc. (Mining) A.M.S. (Retired)
Mining Consultant RQP

of the State Government may require the lessee/lessees to pay for any trees or timber felled and utilised by him/them at the rates specified by the Deputy Commissioner/Collector of the District.

4. Notwithstanding anything in this Schedule contained the lessee/lessees shall not enter upon any reserved forest included in the said lands without previous sanction in writing of the District Forest Officer nor fell cut and use any timber or trees without obtaining the sanction in writing of that Officer nor otherwise than in accordance with such conditions as the State Government may prescribe.

To enter upon reserved forests.

5. The lessee/lessees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within a distance of 50 meters from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concerned or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the Deputy Commissioner/Collector or any Officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions restrictions and conditions either general or special which may be attached to such permission. The said distance of 50 meters shall be measured in the case of railway reservoir or canal horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no working shall be carried on within a distance of 10 meters of the outer edge of the cutting except with the previous permission of the Deputy Commissioner/Collector or other officer duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission.

No mining operations within 50 meters of public works etc.

Explanation:—For the purpose of this clause the expression 'Railway Administration' shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railway Act, 1890, by Section 3 of the Sub-section 4 of that Act. 'Public Road' mean a road which has been constructed by artificially surfaced as distinct from a track resulting from repeated use. Village road will include any track shown in the Revenue record as village road.

6. The lessee/lessees shall allow existing and future holders of Government licenses or leases over any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lessee/lessees reasonable facilities of access thereto.

Facilities for adjoining Government licenses & leases.

PROVIDED THAT no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licenses or leases to the operations of the lessee/lessees under these presents and fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be made to the Lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason of the exercise of his liberty.

PART IV

Liberty Power and Privileges reserved to the State Government

1. Liberty and power for the State Government or to any lessee or persons authorised by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to search for win work dig get raise dress process

To work other mines etc.

ROD
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

75-B

[Signature]
V. K. MACHHARIA
B.Sc. (Mining) - AISM (Mining), FCCM ARRI
Consultant / RQP

Name of mineral	Dead rent fixed per hectare lands	Area of demised land	Dead rent payable Rs.	Total dead rent payable in a year Rs.
1. COAL		4341.57	As per rates proscribed in Schedule IV	
2.		across OR	of the Mineral Concession Rules, 1960	
3.		1756.954		
		Hectares		

(Here insert the manner in which and the time at which the dead rent, surface rent, and water rate should be paid).

Half yearly payment on 15th January and 15th July of each year at the Government Treasury at Gandhinagar by challan.

3. Subject to the provision of clause (1) of this Part, the lessee/lessees shall during subsistence of this lease pay to the State Government at such times and in such manner as the State Government may prescribe royalty in respect of any mineral/minerals removed by him/them from the leased area at the rate for the time being specified in the Second Schedule to the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act 1957.

Rate & mode of payment of royalty.

4. The lessee/lessees shall pay rent and water rate to the State Government in respect of all parts of the surface of the said lands which shall from time to time be occupied or used by the lessee/lessees under the authority of these presents at the rate of Rs. as may be fixed and Rs. respectively per annum per hectare of the area so occupied or used and so in proportion for any area less than an hectare during the period from the commencement of such occupation or use until the area shall cease to be so occupied or used and shall as far as possible restore the surface land so used to its original condition. Surface rent and water rate shall be paid as hereinafter detailed in clause (2) PROVIDED THAT no such rent/water rate shall be payable in respect of the occupation and use of the area comprised in any roads or ways to which the public have full right of access.

Payment of surface rent & water rate.

by the Government from time to time

PART VI

Provisions relating to the Rents and Royalties

1. The rent, water, rate and royalties mentioned in Part V of this Schedule shall be paid free from any deductions to the State Government at Gandhinagar Treasury in such manner as the State Government may prescribe PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed that Rs. 1,000/- the balance standing to the credit of the lessee/lessees on account of the deposit made by him/them as a licensee/licensees over and area which included the said lands shall be retained and accepted by the State Government in satisfaction of the rents and royalties mentioned in Part V until they reach that amount.

Rent and Royalties to be free from deduction etc.

2. For the purposes of computing the said royalties the lessee/lessees shall keep a correct account of the mineral/minerals produced and despatched. The accounts as well as the weight of mineral/minerals in stock or in the process of export may be checked by an officer authorized by the Central or State Government.

Mode of computation of royalty.

Rep
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

75-D

V. K. MACCHERIAL
B.Sc. (Mining), AISM (Mumbai) FICM
Mining Consultant / RQP

convert and carry away minerals other than the said minerals and any other substances and for those purposes to sink drive make erect construct maintain and use such pits shafts inclines drifts levels and other lines waterways airways water courses drains reservoirs engines machinery plant buildings canals tramways railways roadways and other works and conveniences as may be deemed necessary or convenient.

PROVIDED THAT in the exercise of such liberty and power no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties powers and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be made to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason or in consequence of the exercise of such liberty and power.

To make railways and roads.

2. Liberty and power for the State Government or any lessee or person authorised by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to make upon over or through the same any railways, tramways roadways or pipelines for any purpose other than those mentioned in Part II of these presents and to get from the said lands stones gravel earth and other minerals for making maintaining and repairing such railways tramways and roads or any existing railways and roads and to go and repass at all times with or without horses, cattle or other animals, carts, wagons, carriages, locomotives or other vehicles over or along any such railways, tramways, roads lines and other ways for all purposes and as occasion may require, provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties powers and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason or in consequence of the exercise by such lessee or person of such liberty and power.

PART V

Rents and Royalties reserved by this Lease

To pay dead rent or royalty, whichever ever is greater.

1. The lessee shall pay, for every year, except the first year of the lease year, dead rent as specified in clause 2 of this part in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay the dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher in amount but not both.

Rate of mode of payment of dead rent.

2. Subject to the provisions of clause (1) of this Part, during the subsistence of the lease, the lessee/lessees shall pay to the State Government annual dead rent at the following rate/rates or at such revised rate/rates which may be communicated in writing to the lessee/lessees by the State Government per mineral per hectare of the land defined and described in Part I of this Schedule :-

ROD
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

75-C

V. K. M. S.
Sc (Mining), A.S. & M.
Mining Consultant

Handwritten text along the right margin, possibly a file number or reference code.

(Here specify the mode of arriving at sale price/prices at pits
mouth of mineral/minerals).

Course of action if
rents and royalties are
not paid in time.

3. Should any rent, royalty or other sums due to the State Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessee/lessees within the prescribed time, the same may be recovered on a certificate of such officer as may be specified by the State Government by general or special order, in the same manner as an arrear of land revenue.

PART VII

The Covenants of the Lessee/Lessees

Lessee to pay rents &
royalties, taxes etc.

1. The lessee/lessees shall pay the rent, water rate and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in the PARTS V & V of these presents and shall also pay and discharge all taxes, rates, assessments and impositions whatsoever being in the nature of public demands which shall from time to time be charged, assessed or imposed by the authority of the Central and State Governments upon or in respect of the premises and works of the lessee/lessees in common with other premises and works of the like nature except demands for land revenues.

To maintain and keep
boundary marks in
good order.

2. The lessee/lessees shall at his/their own expense erect and at all times maintain and keep in repair boundary marks and pillars according to the demarcation to be shown in the plan annexed to this lease. Such marks and pillars shall be sufficiently clear of the shrubs and other obstructions as to allow easy identification.

The commence opera-
tions within a year &
work in a workman
like manner.

3. Unless the State Government for good cause permits otherwise, the lessee/lessees shall commence operation within one year from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of this lease search for, win, work and develop the said minerals without voluntary intermission in a skilful and workman like manner and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops buildings structures or other property thereon. For the purposes of this clause operations shall include the erection of machinery laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine.

To indemnify Govern-
ment against all
claims.

4. The lessee/lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be done by him/them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

To secure and keep in
good condition pits,
shafts etc.

5. The lessee/lessees shall during the subsistence of this lease well and sufficiently secure and keep open, with timber or other durable means all pits shafts and workings that may be made or used in the said lands and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the State Government round every such pit shaft or working

RGP
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

76

K. MACHHARIAI
Mineral) NSM (Mining) FCIM
Consultant / ROP

DDDDDDDDDD

whether the same is abandoned or not and shall during the same period keep all workings in the said lands except such as may be abandoned accessible free from water and foul air as far as possible.

6. The lessee/lessees shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as the case may be any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal road and any other public works or structure.

To strengthen and support the mine to necessary extent

7. The lessee/lessees shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting examining surveying and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and work effectually assist such officer agents servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Governments as the results of such inspection or otherwise may from time to time see fit to impose.

To allow inspection of workings

8. The lessee/lessees shall without delay send to the Deputy Commissioner/Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously effecting or endangering life and property which may occur in the course of the operations under this lease.

To report accidents

9. The lessee/lessees shall report to the State Government the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease within sixty days of such discovery along with full particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee/lessees shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained therefor.

To report discovery of other minerals

10. The lessee/lessees shall at all time during the said term keep or cause to be kept at an office situated upon or near the said lands correct and intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time:--

To keep records and accounts regarding production & employees etc.

- (1) Quantity and quality of the said mineral/minerals realised from the said lands.
- (2) Quantity of the various qualities of ores beneficiated or converted (for example coal converted into coke).
- (3) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals sold and exported separately.
- (4) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal.

(5) The prices and all other particulars of all sales of said mineral/minerals.

The number of persons employed in the mines or works or upon the said lands specifying nationality, qualifications and pay of the technical personnel.

RQP
AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

V. K. MACHHARIA
B.Sc. (Mining), AISM (Mining)
Mining Consultant / RQP

(7) Such other facts, particulars and circumstances as the State or Central Governments may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such times as the Central and State Governments may appoint true and correct abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the State Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the Central Government or State Government shall in that behalf appoint to enter into and have free access to the said officers for the purpose of examining and inspecting the said books of accounts plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom.

To maintain plans etc.

11. The lessee/lessees shall at all times during the said term maintain at the mine office correct intelligible up-to-date and complete plans and sections of the mines in the said lands. They shall show all the operations, and workings and all trenches, pits and drillings made by him/them in the course of operations carried by him/them under the lease, faults and other disturbances encountered and geological data and all such plans and sections shall be amended and filled up by and from actual surveys to be made for that purpose at the end of twelve months or any period specified from time to time and the lessee/lessees shall furnish free of charge to the Central and State Governments true and correct copies of such plans and sections whenever required. Accurate records of all trenches, pits and drillings shall show:—

- (a) The subsoil and strata through which they pass.
- (b) Any mineral encountered.
- (c) Any other matter of interest and all data required by the Central and State Governments from time to time.

The lessee/lessees shall allow any officer of the Central or State Government authorised in this behalf by the Central Government, to inspect the same at all reasonable times. He/they shall also supply when asked for by the State Government/the Coal Controller/the Director, Geological Survey of India/The Director, Indian Bureau of Mines, a composite plan of the area showing thickness, dip, inclination etc. of all the seams as also quantity of reserves quality-wise.

Act LXI of 1957

12. The lessee/lessees shall be bound by such rules as may be issued from time to time by the Government of India under Section 18 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act LXXI of 1957) and shall not carry on mining or other operations under the said lease in any way other than as prescribed under these rules.

To give the lessee
benefit

13. Unless specifically exempted by the State Government the lessee/lessees shall provide and at all times keep at or near the pit head or each of the pit heads at which the said minerals shall be brought to bank a properly constructed and efficient weighing machine and shall weigh or cause to be weighed thereon all the said minerals from time to time brought to bank sold, exported and converted and also the converted products and shall at the close of each day also the total weights, ascertained by such means of the said minerals and products raised sold exported and converted during the last twenty four hours to be entered in the aforesaid books. The lessee/lessees shall permit the State Government at a

Sub Area Manager
TANDSI SUB AREA

76-B

76-R

W. K. MACHHARIA
(Mining), A.S.M. (Mining)/FCOM
Mining Consultant / RCP

प्राप्त के पत्रिका नुमा
के अर्थात् यह

the said term to employ any person or persons to be present at the weighing of the said minerals as aforesaid and to keep accounts there of and to check the accounts kept by the lessee/lessees. The lessee/lessees shall give 10 (Sixty) days previous notice in writing to the Deputy Commissioner/Collector of every such measuring or weighing in order that he or some officer on his behalf may be present thereat.

14. The lessee/lessees shall allow any person or persons appointed in that behalf by the State Government at any time or times during the said term to examine and test every weighing machine to be provided and kept as aforesaid and the weights used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order and if upon any such examination or testing any such weighing machines or weights shall be found incorrect or out of repair or order the State Government may require that the same be adjusted, repaired and put in order by and at the expense of the lessee/lessees and if such requisition be not complied with within fourteen days after the same shall have been made, the State Government may cause such weighing machines or weights to be adjusted, repaired and put in order and the expense of so doing shall be paid by the lessee/lessees to the State Government on demand and if upon any such examination or testing as aforesaid any error shall be discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the State Government such error shall be regarded as having existed for three calendar months previous

To allow test of weighing machine.

Copy of memorandum No. 9240/9091/III Dated the 05th December 1965 from the Natural Resources Department (M.P.) Bhopal. addressed to the Collector Chhindwara.

According to the existing provision no compensation for surface disturbance for Govt. Land is recoverable from the lessee. Also this cause considerable loss to the State Government, the position has been examined in consultation with the Government of India and it has been held that the compensation could be recovered in such cases if suitable provision is made in Mining lease/ Quarry lease agreement. State Govt. has accordingly therefore decided to substitute the existing clause part VII of Mining lease agreement Form 'K' (Mineral Concession Rule 1960) as under:-

15- The Lessee/ Lessees shall make and pay reasonable satisfaction and compensation for all damage injury or disturbance or person or property situated both in private and Government land which may be done by or on the part of lessee / lessees in exercise of the liberties and power granted by these provisions and shall at all times save harmless and keep indemnified the State Government free and against all suits claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of such damage, injury or disturbance. In case of Govt. Land the Lessee shall grant compensation equal to sixty or fifty times of the Land Revenue of (That may be assessed in case it has not been assessed) in case of lessee of 20 and 30 or and 30 years respectively.

minerals for the purpose of getting working developing and carrying away the same provided that the lessee/lessees shall receive reasonable compensation for any damage or injury which he they may sustain by reason or in consequence of the use of such passage by such lessees or holders of prospecting licences.

17. (1) The lessee/lessees shall not, without the previous consent in writing of the State Government, which in the case of a mining lease

Transfer of lease.

24. 11/11/65
SI SEB... AREA

STACHPARIAL
(Mining), FCCM

in respect of any mineral specified in Schedule I to the Act shall not be given except after previous approval of the Central Government -

- (a) assign, sublet, mortgage or in any other manner, transfer the mining lease or any right, title or interest therein, or
- (b) enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly-financed to a substantial extent by, or under which the lessee's operations or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of persons other than the lessee/lessees.

(2) Without prejudice to the above provisions, the lessee/lessees may, subject to the conditions specified in the proviso to rule 35, of the said rules transfer this lease or any right, title or interest therein, to a person holding a certificate of approval and an income tax clearance certificate from the Income tax Officer concerned, on payment of a fee of rupees one hundred to the State Government.

Provided that the lessee/lessees shall make available to the transferee the original or certified copies of all plans of abandoned working in the area and in a belt 65 metres wide surrounding it.

(3) The State Government, may, by order in writing determine the lease at any time if lessee/lessees has/have in the opinion of the State Government, committed a breach of any of the above provisions or has/have transferred the lease or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with clause (2).

Provided that no such order shall be made without giving the lessee/lessees a reasonable opportunity of stating his/their case.

x Transferred or
al by Trust
then firm or

18. The lease shall not be controlled and the lessee/lessees shall not allow themselves to be controlled by any Trust, Syndicate, Corporation Firm or person except with the written consent of the Central Government. The lessee/lessees shall not enter into or make any arrangement compact or understanding whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly financed by or under which the lessee/lessees' operations or undertakings will or may be carried on directly or indirectly by or for the benefit of or subject to the control of any Trust, Syndicate Corporation Firm or person unless with the written sanction given prior to such arrangement compact or understanding being entered into or made of the Central Government and any or every such arrangement compact or understanding as aforesaid (entered into or made with such sanction as aforesaid) shall only be entered into upon the other party or parties thereto that on the occasion of a state of emergency of which the President of India in his direction shall be the sole judge it shall be terminable if so required in writing by the State Government and shall in the event of any such requisition being made be forthwith thereafter determined by the lessee/lessees accordingly.

760
VAGER
AREA

shall deposit
additional
security.

19. Whenever the security deposit of Rs. 1,000/- Rs. 500/- or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the Central or State Government pursuant to the power in hereinafter declared in that behalf the lessee/lessees shall deposit with the Government such further sum as may be sufficient unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government upto the sum of Rs. 1,000/- Rs. 500/-

76-D

V. K. MA...
B.Sc. (Mining) ...
Mining Consultant / ROP

20. The lessee/lessees shall at the expiration or sooner determination of the said term or any renewal thereof deliver upto the State Government all mines, pits, shafts, inclines, drifts, levels, water ways, airways and other works now existing or hereafter to be sunk or made on or under the said lands except such as have been abandoned with the sanction of the State Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery plant, buildings, structures, other works and conveniences which at the commencement of the said terms were upon or under the said lands and all such machinery set up by the lessee/lessees below ground which cannot be removed without causing injury to the mines or works under the said lands (except such of the same as may with the sanction of the State Government has become disused) and all buildings and structures of bricks or stone erected by the lessee/lessees above ground level in good repair order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.

Delivery of working in good order to State Government after termination of lease.

21. (a) The State Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by notice in writing to the lessee/lessees) of pre-emption of the said mineral (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lessee/lessees and the lessee/lessees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at all times in the manner and at place specified in the notice exercising the said right.

Right of pre-emption.

(b) Should the right of pre-emption conferred by this present provision be exercised and a vessel chartered to carry the minerals or products thereof procured on behalf of the State Government or the Central Government be detained on demurrage at the port of loading the lessee/lessees shall pay the amount due for demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the State Government shall be satisfied that the delay is due to causes beyond the control of the lessee/lessees.

(c) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre-emption PROVIDED THAT in order to assist in arriving at the said fair market price the lessee/lessees shall if so required furnish to State Government for the confidential information of the Government particulars of the quantities, descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.

(d) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole Judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof), the State Government with the consent of the Central Government from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee/lessees) forth with take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the lessee/lessees on or in connection with the said lands or operations under this lease and during such possession or control the lessee/lessees shall conform to and obey all directions given

REAR
VDSI

V. K. MACHHARIA
(Mining), AISM (Mining), FCCI
consultant / RQP

REAR
VDSI

on behalf of the Central Government or State Government regarding the use of employment of such works, plants, premises and minerals PROVIDED THAT fair compensation which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause and PROVIDED ALSO that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this lease.

employment of
foreign national

22. The lessee/lessees shall not employ, in connection with the mining operations any person who is not an Indian national except with the previous approval of the Central Government.

recovery of expenses
incurred by the State
Government

23. If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried out or performed by the lessee/lessees be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee/lessees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

Furnish of geophysical
data

24. The lessee/lessees shall furnish :-

- (a) all geophysical data relating to mining fields or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, collected by him/them during the course of mining operations to the Director, Geological Survey of India, Calcutta.
- (b) all informations pertaining to investigations of radia active minerals collected by him/them during the course of mining operations to the Secretary, Department of Atomic Energy, New Delhi.

Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the mining lease.

PART VIII

The Covenants of the State Government

lessee/lessees may
hold and enjoy rights
quietly

1. The lessee/lessees paying the rents, water rate and taxes hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee/lessees to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the State Government or any person rightfully claiming under it.

acquisition of land of
third parties & com-
pensation thereof

2. If in accordance with the provision of clause (4) of Part VII of this Schedule the lessee/lessees shall offer to pay an occupier of the surface of any part of the said lands compensation for any damage or injury which may arise from the proposed operations of the lessee/lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the right and powers reserved to the State Government and the same to the lessee/lessees by these presents and the lessee/lessees shall refer the matter to the State Government and shall deposit with the

Sub AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

V. K. MACHHARJAL
(Mining) AISM (Mining) P.O.
Mining Consultant / P.O.

amount offered as compensation, and if the Central State Government are satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it is not so satisfied and lessee/lessees shall have deposited with it such further amount as the State and Central Governments shall consider fair and reasonable the State Government shall order the occupier to allow the lessee/lessees to enter the land and to carry out such operations as may be necessary for the purpose of this lease. In assessing the amount of such compensation the State Government shall be guided by the principles of the Land Acquisition Act.

3. Where the mining lease relates to any mineral not specified in Schedule I to the Act, it shall be renewable for one period not exceeding the period specified in Sub-section (2) of Section 8, at the option of the lessee/lessees.

To renew.

Provided that the State Government may for reasons to be recorded in writing reduce the area applied for.

If the lease is in respect of minerals specified in Schedule I to the Act, renewal will be subject to the prior approval of the Central Government.

If the lessee/lessees be desirous of taking a renewed lease of the premises hereby demised or of any part or parts of them for a further term from the expiration of the term hereby granted and is otherwise eligible he/they shall prior to the expiration of the last mentioned term give to the State Government six calendar months previous notice in writing and shall pay the rents, rates and royalties hereby reserved and shall observe and perform the several covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee/lessees to be observed and performed upto the expiration of the term hereby granted. The State Government on receipt of application for renewal, shall consider it in accordance with Rule 28 of the said rules and shall pass orders as it deems fit. If renewal is granted, the State Government will at the expense of the lessee/lessees and upon his executing and delivering to the State Government i) required a counterpart thereof execute and deliver to the lessee/lessee a renewed lease of the said premises or part thereof for the further term of 30 (Thirty) years at such rents, rates and royalties and on such terms and subject to such rents, rates and royalties and on such terms and subject to such covenants and agreements, including this present covenant to renew as shall be in accordance with the Mineral Concessions Rules, 1960, applicable to COAL (name of minerals) on the day next following the expiration of the term hereby granted.

4. The lessee/lessees at any time determine this lease by giving not less than 12 calendar months notice in writing to the State Government or to such officer or authority as the State Government may specify in this behalf and upon the expiration of such notice provided that the lessee/lessees shall upon such expiration tender and pay all rents, water rates, royalties, compensation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other person or persons and shall deliver these presents to the State Government then this lease and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

Liberty to determine the lease.

REP
SUB AREA

77-A

V. K. MACHTARIAL
B.Sc. (Mining), AISM (with Dip. F.C.M.)
Mining Consultant / RQP

4. (a) The State Government may on an application made by the lessee permit him to surrender one or more minerals from his which is for a group of minerals on the ground that deposits of that minerals have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer possible to work the minerals economically, subject to the condition that the lessee :—(a) makes an application for such surrender of minerals at least six months before the intended date of surrender and
(b) gives an undertaking that he will not cause any hinderance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a mining lease for that mineral.

Refund of security deposits.

5. On such date as the state Government may elect within 12 calendar months after the determination of this lease or of any renewal thereof, the amount of the security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the security deposit.

PART IX
General Provisions

Obstructions to inspection.

1. In case the lessee/lessees or his/their transferee/assignee does/do not allow entry or inspection by the officers authorised by the Central or State Government under clauses (i), (j), or (l) of Sub rule (1) of Rule 27 of said rules, the State Government shall give notice in writing to the lessee/lessees requiring him/them to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and his/their security deposit forfeited, and if the lessee/lessees fails/fail to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the State Government, the State Government may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

Penalty in case of default in payment of royalty and breach of covenants.

2. If the lessee/lessees or his/their transferee or assignee makes/ make any default in payment of rent or water rate or royalty as required by Section 9 of the Act or commits a breach of any of the conditions and covenants other than those referred to in covenant (1) above, the State Government shall give notice to the lessee/lessees requiring him/them to pay the rent, water rate, royalty or remedy the breach, as the case may be within sixty days from the date of receipt of the notice and if the rent, water rate and royalty are not paid or the breach is not remedied within such period, the State Government may without prejudice to any proceedings that may be taken against him/ them, determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

Penalty for repeated breaches of covenants.

3. In cases of repeated breaches of covenants and agreements by the lessee/lessees for which notice has been given by the State Government in accordance with clause (1) and (2) aforementioned on earlier occasion, the State Government without giving any further notice, may impose such penalty not exceeding twice the amount of annual dead rent specified in clause (2) Part V.

Failure to fulfil the terms of leases due to "Force Majeure".

4. Failure on the part of the lessee/lessees to fulfil any of the terms and conditions of this lease shall not give the Central or State Government any claims against the lessee/lessees or deemed a

POP
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

77-B

V. K. MACHHARJEE
Mining Consultant / POP

breach of this lease, in so far as such failure is considered by the said Government to arise from *force majeure*, and if through *force majeure* the fulfillment by the lessee/lessees of any of the terms and conditions of this lease be delayed, the period of such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression "*Force Majeure*" means Act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire and any other happening which the lessee/lessees could not reasonably prevent or control.

5. The lessee/lessees having first paid and discharged the rents, rates and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six calendar months whereafter (unless the lease shall be determined under clause (1) and (2) of this part and in that case at any time not less than three calendar months nor more than six calendar months after such determination) take down and remove for his/their own benefit all or any engines, machinery, plants, buildings, structures, tramways, railways and other works erection and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee/lessees in or upon the said lands and which the lessee/lessees is/are not bound to deliver to the State Government under clause 20 of Part VII of this Schedule and which the State Government shall not desire to purchase.

Lessee/lessees to remove their properties on the expiry of lease.

6. If at the end of six calendar months after the expiration or sooner determination of the said term under the provision contained in clause (4) of Part VIII of this Schedule become effective there shall remain in or upon the said land any engines, machinery plant, buildings, structures, tramways, railways and other works erections and conveniences of other property which are not required by the lessee/lessees in connection with operations in any other lands held by him/them under prospecting licence or mining lease the same shall if not removed by the lessee/lessees within one calendar month after notice in writing requiring their removal has been given to the lessee/lessees by the State Government be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee/lessees in respect thereof.

Forfeiture of property left more than six months after determination of lease.

7. Every notice by these presents required to be given to the lessee/lessees shall be given in writing to such person resident on the said lands as the lessee/lessees may appoint for the purpose of receiving such notice and if there shall have been no such appointment then every such notice shall be sent to the lessee/lessees by registered post addressed to the lessee/lessees at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessee/lessees may from time to time in writing to the State Government designate for the receipt of notices and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the lessee/lessees and shall not be questioned or challenged by him.

V. K. MACHHARIA
B.Sc. (Mining), AISM (Mining), FCCM
Mining Consultant / RQP

8. If in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under Chapter VII of the Mineral Concession Rules, 1960, the lessee/lessees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the lessee/lessees in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

Immunity of State Government from liability to pay compensation

9. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised land is Rs. 10,000/- per year.

COLLECTION,
CHHINDWARA

LA 1147
SUB AREA

breach of this lease, in so far as such failure is considered by the said Government to arise from *force majeure*, and if through *force majeure* the fulfilment by the lessee/lessees of any of the terms and conditions of this lease be delayed, the period of such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression "*Force Majeure*" means Act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire and any other happening which the lessee/lessees could not reasonably prevent or control.

5. The lessee/lessees having first paid and discharged the rents, rates and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six calendar months whereafter (unless the lease shall be determined under clause (1) and (2) of this part and in that case at any time not less than three calendar months nor more than six calendar months after such determination) take down and remove for his/their own benefit all or any engines, machinery plants, buildings, structures, tramways, railways and other works erection and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee/lessees in or upon the said lands and which the lessee/lessees is/are not bound to deliver to the State Government under clause 20 of Part VII of this Schedule and which the State Government shall not desire to purchase.

Lessee/lessees to remove/transport their property on the expiry of lease.

6. If at the end of six calendar months after the expiration or sooner determination of the said term under the provision contained in clause (4) of Part VIII of this Schedule become effective there shall remain in or upon the said land any engines, machinery plant, buildings, structures, tramways, railways and other works erections and conveniences of other property which are not required by the lessee/lessees in connection with operations in any other lands held by him/them under prospecting licence or mining lease the same shall if not removed by the lessee/lessees within one calendar month after notice in writing requiring their removal has been given to the lessee/lessees by the State Government be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee/lessees in respect thereof.

Transferable of property left more than six months after determination of lease.

7. Every notice by these presents required to be given to the lessee/lessees shall be given in writing to such person resident on the said lands as the lessee/lessees may appoint for the purpose of receiving such notice and if there shall have been no such appointment then every such notice shall be sent to the lessee/lessees by registered post addressed to the lessee/lessees at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessee/lessees may from time to time in writing to the State Government designate for the receipt of notices and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the lessee/lessees and shall not be questioned or challenged by him.

V. K. MACCUMARIAL
B.Sc. (Mining), AISM (Mining), FCCM
Mining Consultant / RQP

8. If in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under Chapter VII of the Mineral Concession Rules, 1960, the lessee/lessees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the lessee/lessees in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

Immunity of State Government from liability to pay compensation

9. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised land is Rs. 10,000/- per year.

COLLECTOR, CHINDIWARA

RQP
SUB AREA
TANDSI SUB AREA

10. The lessee/lessees hereby agrees/agree to lease out to the Coal Mines Labour Housing Board constituted under the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (hereinafter called the Board) such plot or plots of surface land in the said areas as may be required by the said Board for construction of houses for coal miners for a period of forty years or till the expiry of the terms of mining lease/leases whichever is earlier at a nominal rent of Re. 1/- per annum and to hold himself/themselves responsible for the proper maintenance and repairs of the houses constructed on the said plot/plots and further undertakes/undertake to pay and discharge all rents, rates, taxes and other charges which are now or hereafter may be payable in respect of the said premises or buildings to be erected thereon by the landlord or tenant and further undertakes/undertake to fulfil the terms and conditions laid down by the New Housing Scheme for Coal Miners or or any other housing scheme of the Board, as amended from time to time. The lessee/lessees further stipulates/stipulate if the Board has already constructed houses on any portion/portions of the land taken from previous lessee/lessees the lessee/lessees agrees/agree to accept the said existing lease/leases as having been granted by this lessee/lessees and to renew the said lease/leases for a period which may be necessary to complete 40 years under the said terms and conditions as contained in the previous lease/leases by the previous lessee/lessees.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above-written.

COLLECTOR, CHHINDWARA
 Signed by
 COLLECTOR, CHHINDWARA

for or on behalf of the Governor/President of India
 in the presence of.

Witnesses:

1. [Signature]
 2. [Signature]

For COAL INDIA LTD.,
 General Manager,
 Kanhan Area,
 LESSEE.

Witnesses:

1. [Signature]
 2. [Signature]

REP
 SUB AREA MANAGER
 CHANDSI SUB AREA
 Executive Magistrate,
 For District Magistrate, Chhindwara.
 V. K. KACHHARIA
 a.Sc. (Mining), A.S. (Mining), F.C.M.
 Mining Consultant / RQP

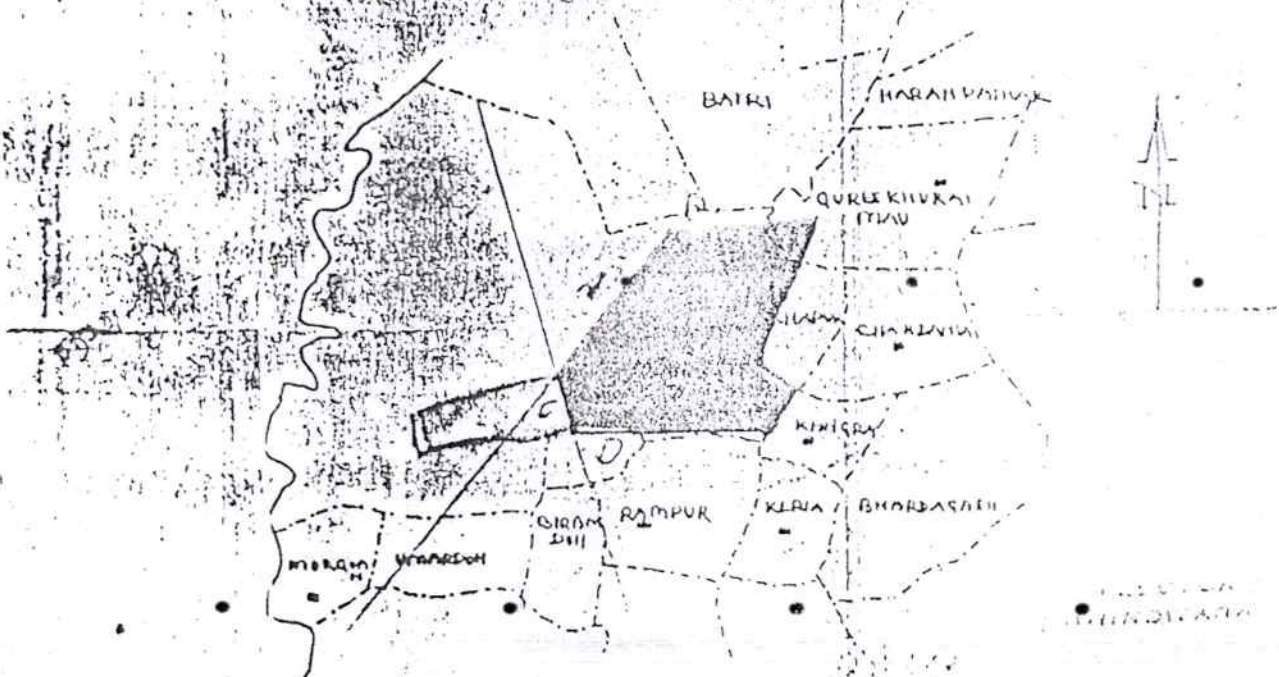
77-D

1:56320
1:12920

PLAN SHOWING MOUZAS

SCALE 1" = 2 MILES

PLAN SHOWING THE ESTIMATED LOCATION & SITUATION OF AREA APPLIED IN VILLAGE KUSUMPATH & NON KHARAK, IN TAHSILDIST. CHHINDWARA.



AND FOUND CORRECT

LEGEND

AREA APPLIED FOR M.L. BY COAL MINES AUTHORITY LTD. IN UNSURVEYED MOUZAS KUSUMPATHAR AND NONKHARAK SHOWN (HACHED RED)

UNSURVEYED VILLAGE PART VILLAGE AREA
 KUSUMPATHAR AREA 1236170 ACRES
 NON KHARAK " " 62270 " "
 TOTAL AREA OF BOTH THE VILLAGES 11986040 ACRES

77-E

RGP
 SUB AREA MANAGER
 TANDSI SUB AREA

V. K. MACHMARIAL
 B.Sc. (Mining), AISM (Mining), FCCM
 Mining Consultant / RQP



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230139
CG-DL-E-04102021-230139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]
No. 575]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(vii) "खान का परिचालन" से पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से विस्फोटन, उत्खनन, कर्तन या खुरचन के पश्चात् प्राप्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या असम्मिलित मामूरी अभिप्रेत है;'

- मूल नियमों में नियम 24ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"24ग. सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान किए गए खनन पट्टे की अवधि.—

- खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् कोयले या लिग्नाइट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे।

(2) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व कोयले या लिग्नाइट के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम में निहित या उसे प्रदत्त सभी विद्यमान खनन पट्टे 50 वर्ष के लिए या 31 मार्च, 2030 तक, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, प्रदत्त किए गए समझे जाएंगे।

(3) राज्य सरकार, इस संबंध में खनन पट्टे के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए आवेदन पर खनिज पट्टे को एक समय में बीस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाएगी:

परंतु राज्य सरकार विहित समय सीमाओं के पश्चात् विस्तार के लिए आवेदन में देरी को माफ कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टे के अवधि का विस्तार नहीं प्रदान किया जाएगा जो निविदा के माध्यम से चयनित की गई है।

(4) यदि राज्य सरकार द्वारा उपनियम (3) में उल्लिखित समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए किया गया कोई आवेदन पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व निपटाया नहीं जाता है, तो उस पट्टे की अवधि उस पर राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किए जाने तक विस्तृत हुई समझी जाएगी।

(5) सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के आरंभ की तारीख पर लंबित थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन समझे जाएंगे और उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।”।

4. मूल नियमों के नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“27क. आवद्ध खान के पट्टाधारी द्वारा कोयले या लिग्नाइट के विक्रय की रीति.—(1) कोई पट्टाधारी जहां आवद्ध प्रयोजन के लिए कोयले या लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है, खान से संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् किमी वित्तीय वर्ष में उत्पादित कोयले या लिग्नाइट की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन यथा अनुज्ञात कुल मात्रा के ऐसे प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट विक्रय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए खान के संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षा उस वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में उक्त संयंत्र द्वारा उपभोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की वार्षिक मात्रा होगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजन के लिए उत्पादित, वितरित, एंड-यूज संयंत्र से संबद्ध उपयोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा और वितरित मात्रा पर अतिरिक्त रकम के संदाय का निर्धारण खान के परिचालन आधार पर किया जाएगा

स्पष्टीकरण 3.—अपशिष्ट, अग्राह्य या मिडलिंग का विक्रय इस नियम द्वारा निर्बंधित नहीं होगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (5) के अनुसार विक्रीत कोयले या लिग्नाइट की मात्रा के लिए पट्टाधारी, राज्य सरकार को स्वामिस्व का संदाय करते समय अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा, जो जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को स्वामिस्व या संदाय अन्य कानूनी संदाय या निविदा दस्तावेज अथवा नीलामी प्रीमियम में विनिर्दिष्ट संदाय, जहां कहीं लागू हो, के अतिरिक्त होगा।

(3) पट्टाधारी पूर्व वित्तीय वर्ष में किए गए विक्रय के लिए किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रण संगठन और राज्य सरकार को प्ररूप द में स्वघोषणा प्रस्तुत करेगा।

(4) किमी कंपनी या निगम को आवंटित कोयले की खानों से कोयले का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा, जिन्हें टैरिफ के लिए प्रतियोगिता बोली के आधार पर शक्ति परियोजना (जिसके अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी है) प्रदान किए गए हैं।”

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट के विक्रय के लिए उपबंध केन्द्रीय सरकार के साथ पट्टाधारी द्वारा किए गए संबंधित करार में विहित पात्रता शर्तों और कार्य कुशलता प्राचलों को प्रभावित नहीं करेंगे।

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 TANDSI SUB AREA

5. मूल नियमों के नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"28. पट्टों का व्यपगमन.—(1) जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ नहीं हुआ हो या उत्पादन या प्रेषण प्रारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की सतत अवधि के लिए समाप्त हो गया हो, खनन पट्टा यथा स्थिति पट्टे के निष्पादन की तारीख से या उत्पादन और प्रेषण की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा।

(2) खनन पट्टे का व्यपगमन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा और पट्टाधारी को भी संसूचित किया जाएगा।

(3) जहां पट्टाधारी खनन अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमर्थ है या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पादन और प्रेषण समाप्त हो जाता है, वह राज्य सरकार को उक्त दो वर्ष की अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पहले उसका कारण दर्शित करते हुए ऐसी दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां पट्टाधारी उपरोक्त नियत समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है वहां दो वर्ष की समाप्ति पर पट्टा व्यपगत हो जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित त्रिनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) वह कारण, जिनसे पट्टाधारी के लिए खनन संक्रियाएं करने या उत्पादन और प्रेषण को जारी रखना असंभव हो गया;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण पट्टाधारी के नियंत्रण के बाहर हैं;

(ग) वह कदम जो पट्टाधारी द्वारा ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए हैं; और

(घ) चाहे गए विस्तार की अवधि।

(5) उपनियम (3) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ दो सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।

(6) राज्य सरकार, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्, उपधारा (3) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से, जिसको खनिज पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो, से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा अनुरोध को स्वीकार करते हुए या खारिज करते हुए कोई आदेश पारित करेगी:

परंतु ऐसा खनिज पट्टा उत्पादन और प्रेषण करने में विफल होने पर या एक वर्ष के लिए बढ़ाई गए अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण जारी रखने में असक्षमता पर व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा विस्तार पूरी पट्टा अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं प्रदान की जाएगी।

(7) राज्य सरकार ऐसा आदेश अभिलिखित करने या जारी करने के पंद्रह दिन के भीतर उपनियम (2) के अधीन अभिलिखित या उपनियम (6) के अधीन जारी आदेश कोयला नियंत्रण संगठन, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और कोयला मंत्रालय को संसूचित करेगी।"

6. मूल नियमों के नियम 28क का लोप किया जाएगा।

7. मूल नियमों के नियम 64ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"64ख प्रसंस्करण के अधीन रहते हुए खनिजों के मामले में रायल्टी के संदाय भुगतान करना और भारित करना- पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्करण को विचार में लाए बिना अप्रसाधित अयस्क खनिजकोयला या लिग्नाइट पर रायल्टी, भारित की जाएगी:

परंतु रायल्टी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर से प्रेषण या उपभोग के समय देय होगी।"

8. मूल नियमों में, नियम 64ग का लोप किया जाएगा।

9. मूल नियमों में, अनुसूची I में, प्ररूप थ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

Attested
3msy
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

6. उत्पादन-शून्य उत्पादन में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में।

क)

ख).....

7. पूर्व खान मूल्य वार श्रेणी में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में।

क)

ख).....

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पूरा नाम

पदनाम: स्वामी/अभिकर्ता/खान इंजीनियर/प्रबंधक।

[फा. सं. 12012/2/2021-पी एस 1]

बी.पी. पति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम दिनांक 23 नवंबर, 1960 की संख्या जी.एस.आर. 1398 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए थे और दिनांक 29 मई, 2020 की संख्या जी.एस.आर. 331(अ) के जरिए अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन:

केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के माध्यम से अंतःस्थापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 की उपधारा (4) को तदनुसार विद्यमान खान के पट्टों की अवधि को विहित करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के मामलों में खान के पट्टों की अवधि को विस्तार करने के लिए सशक्त करती है, विद्यमान पट्टों की अवधि को नियम 24ग की उपधारा (2) में विहित किया गया है और खान के पट्टों के नवीकरण के लिए लंबित आवेदनों को नियम 24ग के उपनियम (5) में खान के पट्टों की अवधि के विस्तार के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के माध्यम से भूतलकी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

G.S.R. 717(E).—In exercise of powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules they shall come into force on the date of their publication in Gazette of India.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viii) “run-of-mine” means the raw, unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting, digging, cutting or scraping from the mineralised zone of a lease area.”

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

3. In the principal rules, after rule 24B the following rule shall be inserted, namely:-

"24C. Period of mining lease granted to Government companies or corporations.—

- (1) All mining leases granted on or after the commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 to a Government company or corporation for coal or lignite shall be for a period of fifty years.
- (2) All subsisting mining leases vested or granted to a Government company or corporation before commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 for coal or lignite shall be deemed to have been granted for fifty years or till 31st March 2030, whichever is later.
- (3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for a further period of twenty years at a time:
Provided that the State Government may condone the delay in application for extension made after the prescribed time limit:
Provided further that no extension of period of mining lease shall be granted to a Government company or corporation that has been selected through auction.
- (4) If an application for extension of mining lease made within the time mentioned in sub-rule (3) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended till the State Government passes an order on the same.
- (5) All applications made by a Government company or corporation for renewal of mining lease which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (3)."

4. In the principal rules, after rule 27, the following rule shall be inserted, namely:-

"27A. Manner of sale of coal or lignite by the lessee of a captive mine.— (1) Any lessee may, where coal or lignite is used for captive purpose, sell coal or lignite up to such per cent. of the total coal or lignite produced in a financial year, as allowed under sub-section (5) of section 8, after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine.

Explanation 1.- For the purpose of this rule it is clarified that the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of coal or lignite consumed in the said plant in that financial year or a part thereof.

Explanation 2.- For the purpose of this rule, quantity of coal or lignite produced, sold, utilised in linked end-use plant and the payment of additional amount on the quantity sold shall be assessed on run-of-mine basis.

Explanation 3.- Sale of any tailings, rejects or middlings shall not be restricted by this rule.

(2) For the quantity of coal or lignite sold in accordance with sub-section (5) of section 8, the lessee shall pay to the State Government, at the time of payment of royalty, an additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act, which shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust or any other statutory payment or payment specified in the tender document or the auction premium, wherever applicable.

(3) Within one month of the end of a financial year, for sale made in the previous financial year, the lessee shall submit to the Nominated Authority, Ministry of Coal, Coal Controller's Organisation and to the State Government, a self-declaration in Form R.

(4) Sale of coal shall not be allowed from the coal mines allotted to a company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Projects)."

Explanation.-For the purpose of this rule, it is clarified that the provision for sale of coal or lignite as prescribed in this rule shall not affect the eligibility conditions and efficiency parameters prescribed in the respective agreements entered into by the lessee with the Central Government.

5. In the principal rules, for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:-

“28. Lapsing of Leases.— (1) Where production and dispatch has not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of production or dispatch, the mining lease shall lapse on the expiry of the period of two years from the date of execution of the lease or as the case may be, discontinuance of the production and dispatch.

(2) The lapsing of the mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.

(3) Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, requesting for an extension of such period of two years by a further period not exceeding one year, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.

(4) Application made under sub-rule (3) shall specify—

- (a) the reasons on account of which it will not be possible for the lessee to undertake mining operations or continue production and dispatch;
- (b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee;
- (c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons; and
- (d) the period of extension sought.

(5) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of two hundred rupees.

(6) The State Government shall, after examining the application, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period of one year:

Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.

(7) The State Government shall communicate to the Coal Controller's Organisation, Nominated Authority and Ministry of Coal the order recorded under sub-rule (2) or issued under sub-rule (6) within fifteen days of recording or issuing of such order.”

6. In the principal rules, rule 28A shall be omitted.

7. In the principal rules, for rule 64B, the following rule shall be substituted, namely:-

“64B. Charging and instance of payment of royalty in case of minerals subjected to processing.— The royalty shall be charged on run-of-mine coal or lignite irrespective of its processing within or outside the leased area:

Provided that the royalty shall be payable at the time of dispatch from or consumption within the leased area.”

8. In the principal rules, rule 64C shall be omitted.

9. In the principal rules, in Schedule I, after Form Q, the following Form shall be inserted, namely:-

Handwritten signature
2nd
 SUB AREA P.M. SGLD
 TANDSI SUB AREA

20.2-143/86-70

GM (CP)

PARYAVARAN BHAWAN, D.G.O. COMPLEX
401/1, 4th Floor, (10000)
LODI ROAD, NEW DELHI-110003

Dated: 15th May, 1981

The Secretary,
Forest Department,
Govt. of Madhya Pradesh
Bhopal,

Subject: Diversion of 299.44 ha. of forest land in Chhindwara district for underground mining of Coal by Western Coalfields Limited (Tandla project).

Sir,
I am directed to refer to your letter No.F-5/15/86/10/3 dated 14.7.80 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Govt. in accordance with section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Govt. under section 3 of the aforesaid Act.

After careful consideration of the proposal of the state Govt. and on the basis of the recommendation of the mentioned Advisory Committee, the Central Govt. hereby conveys its approval under Sec 2 of the Forest (Cons) Act, 1980 for diversion of 299.44 ha. of forest land in Chhindwara district for underground mining of Coal by Western Coalfields Limited subject to the following conditions:

- (i) Legal status of forest land will remain unchanged.
- (ii) No disturbance will be caused to the forest.
- (iii) No work will be done on the surface in the forest area.
- (iv) In order that the construction labour and staff while working on the project in the forest area may not cause destruction to the forest area for meeting their fuelwood needs, the user agency will establish fuelwood depots and will provide fuelwood to them free of cost.
- (v) An undertaking from the Western Coalfields Authorities to the effect that in case subsidence is taking place, the project authorities will provide equal extent of non forest land/funds for raising compensatory afforestation, has to be obtained. Copy of the undertaking given by the project authorities should be submitted to this Ministry.

Yours faithfully,

(G. HARI KUMAR)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'A.E. W.' and '6/11'.

Revenue Dept. for Jaffer the immediate copy for the early Gms. lead

Affected

SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

LANDSI FOREST

ANNEXURE - I

SR. Distt : Palakkad / Taluk : Palakkad
 No. :
 Village :
 Taluk :
 District :
 W.C.L. AREA

Sl. No.	Description	Total Area Hect	Applied for H.L.	Acres	Forest Area in Compt. No.	Hect	Acres	R B V R F L S (H.V.)	Small Tree Rev. Area in	Other Govt. Land Area in	Private Land (Tenancy Land) in	Total Hect	Acres
(1)	Un Surveyed Village	346.00	859.90	422	423	299.44	739.91	48.56	119.99			48.56	119.99
(2)													
(3)													
(4)													
	Total	346.00	859.90										

48.56 Hect/119.99 Acres
 (As v.111.60 are un surveyed)

(1) Total Forest Land
 (2) Total Revenue Land

Total 346.00 859.90

[Signature]
 ASST. SUPERVISOR OFFICER,
 W.C.L. AREA

[Signature]
 STAFF OFFICER (JUNIOR)
 W.C.L. AREA

[Signature]
 DISTRICT MANAGER
 W.C.L. AREA

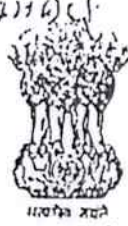
W.C.L. AREA MANAGER
 W.C.L. AREA

संख्या 21] जी.एल.—33001/99

REGISTERED NO. D. L.—33001/99

Ghugur o/c Project-
S.O No 1398-01: 6-5-99.

Tandri Block 48-11(i) c
S.O No. 1398-01-11-5-99



भारत गजट

The Gazette of India

सूचना ब्लॉक-2 & 4 (डि.ए.ए-1)
S.O No 1398-01-11-5-99
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
[No. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1999/ज्येष्ठ 1, 1921
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1999/JYAISTHA 1, 1921

इस भाग में दिए पृष्ठ संख्या की जादी है ताकि यह भाग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

कार्य: लोक शिकायत सेवा पेशन मंत्रालय
(कार्य, और प्रशिक्षण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1999

ना.आ.1367.—भारतीय सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष
पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम
सं. 25) की धारा 6 के साथ मूठित धारा 5 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य
सरकार के गृह (पुलिस) विभाग की दिनांक 01-03-99
की अधिसूचना सं. 3/विधि-6031/98, नं.आ. 2503
द्वारा प्राप्त बिहार राज्य सरकार की सहमति से किन्तु ज्वर
हस्ताक्षर के साथ 28-04-99 को पंजीय और बंटा-
पट्टे प्रस्ताव सं. सं. 115/6-7 के अंतर्गत बिहार राज्य
शाखा-शाखा प्रशासनिक ट्रेनिंग के पदों में उभर जाने संबंधी
दुवेस्ता के लिए प्रकृतिकारण, बिहार जी.आर.सी. एलिया
द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 1367, 1999

(1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 337, 338,
304(ए), 379 संशुद्धित रक्त अधिनियम की धारा 154/
175 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों तथा उद्घात अपराधों
से संबंधित अधवा संसक्त प्रकरणों, पुष्पेरणों और पड्यंतों
तथा उन्ही संशुद्धित अधिनियम में किए गए भववा उन्ही
तथा अधवा संसक्त से उद्घात किन्हीं अन्य अपराधों के
अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण बिहार
राज्य पर करती है।

[सं. 228/14/99-ए.बी.डी.-11]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSION
(Department of Personnel and Training)

S.O. 1367.—in exercise of the powers confer-
ed by sub-section (i) of section 5, read with section

1366 G. 91-1

(1123)

(3) the said Company shall indemnify the Central Government or its Officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the said rights in or over the said land so vesting.

(4) the said Company shall have no power to transfer the said rights in or over the land so vested, to any other persons without the

ment; and

(5) the said Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said rights in or over the land as and when necessary.

[No. 43015/7/92-LSW/PRIW]

K. S. KROPIA, Director

घाटेण

नई दिल्ली, 11 मई, 1999

का.घा. 1400.—कोयला धारक क्षेत्र (प्रजन और विकास) प्राधिकरण, 1957 (1957 जन 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) को धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विभागीय नई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधीनस्थ दिवस 20 जन. प्रा. 1995 तारीख 4 मंगल, 1997 के आदेश के अन्तर्गत संचालित किया गया है। उक्त प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित प्रयुक्तियों में संशोधन का काम उक्त प्रा. के प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) उक्त प्राधिकरण 1366/1999-03

की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मंत्री नियंत्रणों से मुक्त होकर, सांख्यिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निर्धारित हो गए थे;

श्रीर, केन्द्रीय सरकार का यह सन्तुष्ट हो गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे नियंत्रणों और शर्तों का जो केन्द्रीय सरकार इस निम्नलिखित प्रतिरोधित करना उचित समझे अनुपालन करने के लिए राजावत है;

11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि इस प्रकार निर्दिष्ट उक्त भूमि में मा उक्त प्रा. के प्राधिकरण, तारीख 16 मंगल, 1997 में केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निर्दिष्ट बने रहने का बन्नाय, निम्नलिखित नियंत्रणों और शर्तों के अधीन, रहते हुए, उक्त कंपनी में निर्हित हो जाएंगे, अर्थात्:--

(1) उक्त कंपनी, उक्त प्राधिकरण के अधिकारियों के अधीन प्रवर्धित प्रतिकर, व्याज, नुकसानों और शर्तों की मर्तों की याचत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;

(2) उक्त कंपनी द्वारा शर्तों (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अर्देय रकमों का प्रवर्धारण करने के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उचित सभी समय, उक्त सरकारी कंपनी सहन करेगी और इसी प्रकार, इस प्रकार निर्दिष्ट या उनके संबंध में सभी विधिक कार्रवाहियों, जैसे प्रतीत धार्द की याचत उचित सभी समय भी, उक्त कंपनी सहन करेगी;

(4) उक्त कंपनी को, केंद्रीय सरकार के पूर्ण धन सहायता के बिना, उक्त अधिनियम-1 में विहित अधिगूचना की प्रकृति में विनिश्चित अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ;

(5) उक्त कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि में या उक्त पर के अधिकार विनिश्चित क्षेत्रों के लिए दिए

[क्र. सं. 13015/7/92-एनएमएडए/वीआरए(ईएनएम)]

के, एम. प्रोवें, निदेशों

ORDER

New Delhi, the 11th May, 1999.

S.O. 1399.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3408, dated the 2nd December, 1996, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 14th December, 1996, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said rights) vested in the Central Government, and the said rights are free from all encumbrances, under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Naupur, a Government Company (hereinafter referred to as the said Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said rights in or over the land, so vested, shall, with effect from

the 14th December, 1996, instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the said Com-

pany, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (1) the said Company shall reimburse the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act,
- (2) a tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the said Company and, similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights in or over the land, so vesting shall also be borne by the said Company.

812 के अंतर्गत प्रयोजित भूमि सरकार के अधीन
प्रयोजन की अधिनियम का या उक्त अधिनियम 11 अक्टूबर,
1999 में

पृष्ठ क्रमांक 812 पर

प्रादेश के परिच्छेद की छठवीं पंक्ति में

"21 अगस्त 1992 के स्थान पर 31 अगस्त 1999
परिवर्तित।"

पृष्ठ क्रमांक 812 पर

नियंत्रण और शर्तों के अधिनियमित प्रांगों में

(1) में 'अति' के स्थान पर 'अति' परिवर्तित।

(3) में 'अति' के स्थान पर 'अति' परिवर्तित।

(5) में 'पालन करेगी' के स्थान पर 'पालन करेगी'

[सं. 13015/2/88-एम. ए. उ. अ. वि. धार. प्रा. उ. अ.]

के.एम. प्रोफा, निर्देशक

प्रादेश

नई दिल्ली, 11 मई, 1999

धारा (1) के अधीन, सभी किल्लतों से मुक्त होकर,
सांख्यिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे।

धारा, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर सरकारी कंपनी (जिसे
इसमें इसका पश्चात् उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे
निबंधनों धारा शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त
अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए
रजामंद है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, यह निर्देश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि
धारा उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 14
दिसम्बर, 1996 में केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित
रहने की वजाह, निम्नलिखित निबंधनों धारा शर्तों
के अधीन रहने हूए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएगी,
अर्थात् :-

(1) उक्त कंपनी, उक्त अधिनियमों के उपबंधों के
अधीन, धरधारित अधिकार, धारा, मुहसालों धारा बेसी ही
मर्तों की वास्तु किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार
की अधिनियम करेगी ;

(2) उक्त कंपनी द्वारा शर्तों (1) के अधीन, केन्द्रीय
सरकार को संदेय रकमों का प्रसारण करने के प्रयोजन के
लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी
अधिकरण धारा ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त
व्यक्तियों के संबंधों में उक्त सभी व्यय, उक्त सरकारी
कंपनी वहन करेगी धारा शर्तों प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त
भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध
में सभी विधिक कार्यवाहियों, जैसे प्रीस प्रादि की वास्तु
उक्त सभी व्यय भी, उक्त कंपनी वहन करेगी ;

(3) उक्त कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके
पदधारियों की निम्न लिखित शर्तों के अधीन, उक्त
भूमि में या उस पर के अधिकारों के
बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या
उनके विरुद्ध, किसी कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हों,
अधिनियम करेगी ;

धारा 11-1999 -- कायना-धारा 11-1999 (अंश
धारा 11-1999) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)
की धारा 11-1999 (1) में 'अति' के स्थान पर 'अति' परिवर्तित।
भारत सरकार के अधीन मंत्रालय की अधिनियम, संसदा
का प्रा. 3408 तारीख 2 दिसम्बर, 1996 के, भारत
के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11
दिसम्बर, 1996 में कायना भूमि धारा भूमि में या उक्त
पर के अधिकार (जिसे इसमें इससे पश्चात, उक्त भूमि
कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड § ii § में प्रकाशित

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2/12/1996

अधिसूचना

का०आ० 139 केन्द्रीय सरकार ने कोयला पारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 का 20 की धारा 7 की उपधारा § 1 के अधीन भारत के राजपत्र, अंग 2, खंड 3, उपखंड § ii §, तारीख 20 अक्टूबर, 1995 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 853 अ. तारीख 20 अक्टूबर 1995 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में धिनिर्दिष्ट इलाकों की भूमि में, जिसका नाम 542. 557 हेक्टेयर इलाका है या 1340. 713 एकड़ है, खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने तथा उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने अधिकारों की सुरक्षा की थी,

उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार में केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि,

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समझा जा रहा है कि इलाके संलग्न अनुसूची में वर्णित 542. 557 हेक्टेयर इलाका या 1340. 713 एकड़ इलाका नाम वाली भूमि में खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई करने, तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा § 1 द्वारा पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इलाके संलग्न अनुसूची में वर्णित 542. 557 हेक्टेयर इलाका या 1340. 713 एकड़ इलाका नाम वाली भूमि में खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई करने, तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

... 2/...

प्राप्त करने पर परीक्षा करने और ले जाने के अधिकारों के अर्जित की घोषणा

• इस अधिसूचना के अर्जित जाने वाले क्षेत्र के रेकॉर्ड सं० सी-1/33/111/एचआर0/601-496, तारीख 15 अगस्त, 1996 का निरीक्षण कम्प्यूटर, डिंडवाड़ा इमप्य प्रोमो के कार्यालय में या लोयला नियंत्रक, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, बलकल्ला-700001 के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इराजस्टव विभाग, कोलकत्ता, सिविल बाइपास, नागपुर-640001 महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

टांडा व्लाक

कनहन क्षेत्र

जिला डिंडवाड़ा इमप्य प्रोमो

रेकॉर्ड सं० सी-1/33/111/एचआर0/601-496, तारीख 15 अगस्त, 1996
कनहन अधिकार

क्र. सं०	नाम	पारधान्ती संख्यांक	कम्पार्टमेंट संख्यांक	तत्समीन	जिला	क्षेत्र	विस्तार/प्रमाण
1.	करंजगाडी कुडी	312	इनयाई -	बुन्नारदेव	डिंडवाड़ा	61.668	भाग
2.	संरक्षित वन	पी-410	इनयाई	बुन्नारदेव	डिंडवाड़ा	72.150	भाग
3.	संरक्षित वन	पी-424	इनयाई	बुन्नारदेव	डिंडवाड़ा	75.091	भाग
4.	संरक्षित वन	पी-422	इनयाई	बुन्नारदेव	डिंडवाड़ा	46.944	भाग
5.	संरक्षित वन	पी-423	इनयाई	बुन्नारदेव	डिंडवाड़ा	254.147	भाग

... 3/...

भारत के संविधान, भाग 2, खंड 3, उपखंड i में प्रकाशित

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2/12/1995

अधिसूचना

5

का०आ० / 3377 केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 का 20 की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन भारत के संविधान, भाग 2, खंड 3, उपखंड i, तारीख 20 अक्टूबर, 1995 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 853 अ०, तारीख 20 अक्टूबर, 1995 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिचय की भूमि में, जिसका गा० 542. 557 हेक्टेयर इलाका या 1340. 713 एकड़ है, खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने तथा उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए,

केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्वय में उक्त क्षेत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 853 अ०, तारीख 20 अक्टूबर, 1995 द्वारा जारी की है,

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 542. 557 हेक्टेयर इलाका या 1340. 713 एकड़ इलाका या गा० वाली भूमि में खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई करने, तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन प्रस्तावित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 542. 557 हेक्टेयर इलाका या 1340. 713 एकड़ इलाका या गा० वाली भूमि में खनिजों के खनन, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें

... 2/...

प्रमाण करने पर कार्य करने और ले जाने के अधिकारों के अर्जन की घोषणा

उस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के-रेखांक सं० सी-1/ईई/111/एच०आर०/601-496, तारीख 15 अप्रैल, 1996 का निरीक्षण कलकत्ता, सिंदवाड़ा ईमध्य प्रदेश के कार्यालय में या लोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड {राजस्व विभाग}, कोलकत्ता, सिंदवाड़ा, नानपुर-440001 {महाराष्ट्र} के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

टाइप: ब्लॉक

कनहन क्षेत्र

जिला सिंदवाड़ा ईमध्य प्रदेश

रेखांक सं० सी-1/ईई/111/एच०आर०/601-496, तारीख 15 अप्रैल, 1996
कनहन अधिकार

क्र. सं०	नाम	पट्टाधारी	कम्पाटिबल	तालिका	जिला	क्षेत्र	विष्णु
क्र. सं०	नाम	संख्यांक	संख्यांक	संख्यांक	जिला	क्षेत्र	विष्णु
1.	संविधान	पी-412	संख्यांक	सुन्दरदेव	सिंदवाड़ा	61.668	भाग
2.	संविधान	पी-410	संख्यांक	सुन्दरदेव	सिंदवाड़ा	72.150	भाग
3.	संविधान	पी-421	संख्यांक	सुन्दरदेव	सिंदवाड़ा	75.091	भाग
4.	संविधान	पी-422	संख्यांक	सुन्दरदेव	सिंदवाड़ा	76.944	भाग
5.	संविधान	पी-423	संख्यांक	सुन्दरदेव	सिंदवाड़ा	254.147	भाग

... 3/...

संरक्षित वन -- पी-434/जुन्नारदेव हिंदवादा 82.557 भाग
पी-424 नया

कुल क्षेत्र : 542.557 हेक्टेयर
हेलमभाग
या 1370.713 रु.
हेलमभाग

जाम करंजपानी घुची में अर्जित किए गए प्लान संख्यांक : 125 से 170

अर्जित किए गए संरक्षित वन की कम्पार्टमेंट संख्यांक :

पी-410, पी-400 नया भाग, पी- 21/पी-411 नया भाग, पी-422/पी-412 नया
पी-423/पी-413 नया भाग, पी-434/पी-424 नया भाग

सीमा वर्णन :

- क : रेखा बिन्दु "क" से आरंभ होती है और वन कम्पार्टमेंट संख्यांक पी-421/पी-411 नया और पी-410/पी-400 नया से होकर रेखा बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
- ख-ग : रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक पी-410/पी-410 नया से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
- ग-घ : रेखा ग्राम करंजपानी घुची की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
- घ-ड0 : रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक पी-423/पी-413 नया से होकर जाती है और बिन्दु "ड0" पर मिलती है ।
- ड-च : रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक पी-423/पी-413 नया से होकर जाती है फिर करंजपानी घुची और ननकडक ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है तथा बिन्दु "च" पर मिलती है ।
- च-ड1 : रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक पी-423/पी-413 नया के साथ साथ बिन्दु "च" पर मिलती है ।

... 1/...

BE 2021

- ड-ल : रेखा वन कम्पाउण्ड संख्यांक पी-423/पी-417 इनया से होकर ज
हे ओर बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
- ज-झ : रेखा वन कम्पाउण्ड संख्यांक पी-423/पी-413 इनया और पी-434/
पी-424 इनया से होकर जाती है तथा बिन्दु "झ" पर मिलती है ।
- झ-ञ : रेखा वन कम्पाउण्ड संख्यांक पी-434/पी-424 इनया, पी-422/पी-
412 इनया और पी-421/पी-411 से होकर जाती है तथा आरंभिक
बिन्दु "क" पर मिलती है ।

श्रीमती पी. एल. सैनी
अधर सचिव, भारत सरकार

फा. सं. 43015/7/92-एल. एल. डब्ल्यू.

शेखर में,
एवम्भक इतकनी की
भारत सरकार, गुणालय,
रिंग रोड, माधपुरी,
नई दिल्ली

Sr. PC-CA

GOVERNMENT OF INDIA (BEHARAT SARKAR)
MINISTRY OF COAL (KOYLA MANTRALAYA)

New Delhi the 2nd December 1995.

NOTIFICATION

Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, No. S.O. 853(E) dated the 20th October, 1995, published in the extra ordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th October, 1995, under sub-section (ii) of Section-7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 542.557 hectares (approximately) or 1340.713 acres (approximately) the Mining rights in the locality specified in the schedule annexed to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the mining rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 542.557 hectares (approximately) or 1340.713 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the mining rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 542.557 hectares (approximately) or 1340.713 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto are hereby acquired.

The plan bearing number C-1(E)/III/HR/601-496 dated the 15th April, 1996, of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chhindwara, Madhya Pradesh or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700 001 or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra).

Contd.....2/...

:-: 2 :-:

SCHEDULE
TANDSI BLOCK
KANMAR AREA
DISTRICT CHHINDWARA (INDIANA PROVINCE)

(Plan No: 811(E)/III/HR/601-496 dated the 15th April, 1906)

Serial number of the village	of the Forest	Patwari circle number	Compartment number	Tahsil	District	Area in Hectares	Part
	Kamjpani Dhandhi	3/2(New)		Junnar-deo	Chhindwara	61,668	Part
2.	Protected Forest	-	P-410/ P-400(New)	Junnar-deo	Chhindwara	72,150	Part
3.	Protected Forest	-	P-421/ P-411(New)	Junnar-deo	Chhindwara	25,091	Part
4.	Protected Forest	-	P-422/ P-412(New)	Junnar-deo	Chhindwara	46,944	Part
5.	Protected Forest	-	P-413/ P-413(New)	Junnar-deo	Chhindwara	254,147	Part
6.	Protected Forest	-	P-434/ P-424(New)	Junnar-deo	Chhindwara	82,957	Part
Total Area :						542,957	hectares (approximate)
						or	1340.713 a (approximate)

Plot numbers acquired in village Kamjpani Dhandhi : 125 to 170.

Compartment numbers of Protected Forest acquired :

P-400 (New) Part, P-421 (New) Part, P-422/P-412 (New) Part

Boundary description:

Line starts from point 'A' and passes through P-411 (New) and P-410/P-400 (New) and

:-: 3 :-:

- C : Line passes through forest compartment numbers P-410/P-400 (New) and meets at Point 'C'.
- D : Line passes along the eastern boundary of village Karigmani and meets at Point 'D'.
- E : Line passes along the forest compartment number P-423/P-413 (New), and meets at Point 'E'.
- F : Line passes through forest compartment number P-423/P-413 (New), then proceeds along the common village boundary of villages Karigmani, Dhundi and Bankhark and meets at point 'F'.
- G : Line passes along the forest compartment number P-423/P-413 (New) and meets at Point 'G'.
- H : Line passes through forest compartment number P-423/P-413 (New) and meets at point 'H'.
- I : Line passes through forest compartment number P-423/P-413 (New) and P-424/P-424 (New) and meets at point 'I'.
- A : Line passes through forest compartment number P-424 (New), P-422/P-412 (New) and P-421/P-411 (New) and meets at starting Point 'A'.

11, 3

(P.L. Saini) Mrs.
Under Secretary to the Govt. of India.
No. 43015/7/82-LSW

The Manager (Technical),
Government of India Press,
Road, Mayapuri,
New Delhi.

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Mineral Resources Department, Bhopal (MP). It is requested that the notification may be republished immediately in the State Gazette and a copy of the same may be sent to this Ministry.
2. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, with two copies of the plan for

Contd.....4 ...

3. The Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur (with two spare copies).
4. The Director General, Geological Survey of India, Calcutta.
5. The Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh) - with two spare copies along with two copies of the plan for inspection by the interested parties.
6. The Planning Commission, New Delhi.
7. The Regional Manager, Coal India Limited, Flat No. 402-404 (with Mrs. Ansal Bhawan, 10, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi).
8. The Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440 001 (M.S.) (with 20 spare copies).
9. The Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Darbhanga House, Ranchi.
10. The Regional Director, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Jaripatka, Nagpur.
11. For folder.

U. Saini
(P. L. Saini) Mrs.
Under Secretary to the Govt. of India.
No. 43015/7/92-ISM


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938

No. 708]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/ CHAITRA 1, 1938

बोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ. 1170(अ).—केन्द्रीय सरकार ने बोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के बोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का. आ. 3148(अ), तांख 19 नवम्बर, 2015 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तांख 23 नवम्बर, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 204.67 हेक्टर (लगभग) या 505.74 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या खनन अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 204.67 हेक्टर (लगभग) या 505.74 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में खनन अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 204.67 हेक्टर (लगभग) या 505.74 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनन अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या ए-1(ई)/III/एचआर/926-0216, तांख 13 फरवरी, 2016 का निरीक्षण कलक्टर, जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या बोयला नियंत्रक, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट,

1409 GI/2016

(1)

Attorney
[Signature]

SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

तानसी भूमिगत खान का विस्तार

कन्हान क्षेत्र

जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी-1(ई)/111/एचआर/926-0216, तारीख 13 फरवरी, 2016)

खनन अधिकार :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	रेंज/ब्लाक/कम्पार्टमेंट नंबर का नाम	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन (हेक्टर में)				टिप्पणियां
							अभि-धृति	सरकारी	वन	कुल	
1.	करंज-पानी धुन्धी	-	07	-	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	7.840	82.81	-	90.65	संपूर्ण
2.	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 400	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	20.544	20.544	भाग
3.	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 401	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	61.794	61.794	भाग
4.	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 402	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	02.719	02.719	भाग
5.	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 410	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	16.174	16.174	भाग
6.	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 413	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	12.789	12.789	भाग
कुल :							7.840	82.81	114.020	204.670	-

कुल : 204.670 हेक्टर (लगभग)

या 505.74 एकड़ (लगभग)

ग्राम करंजपानी धुन्धी में अर्जित की गई प्लाट संख्यांक :

अभिधृति भूमि : 76, 77, 86, 93, 97, 100, 102, 115, 118, 120 और 123.

सरकारी भूमि : 26 से 75, 78 से 85, 87 से 92, 94 से 96, 98, 99, 101, 103 से 114, 116, 117, 119, 121, 122 और 124.

सीमा क्षेत्र के वन कम्पार्टमेंट संख्यांक : 400(भाग), 401(भाग), 402(भाग), 410(भाग) और 413(भाग).

सीमा वर्णन :

क - ख : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्यांक 401(भाग) से बिन्दु 'क' से आरंभ होती है फिर रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 402(भाग), 410(भाग) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

Attested
SUB AREA TANDSI
TANDSI SUB AREA

- ख-ग-घ : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्याक 410(भाग) से बिन्दु 'ग' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ङ-च- : रेखा, ग्राम कजपानी धुन्दी से बिन्दु 'ङ'-'च'-'छ' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज-झ-ञ- : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्याक 413(भाग) से बिन्दु 'झ'-'ञ'-'ट'-'ठ' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।
- ट-ठ-ड : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्याक 400(भाग) से बिन्दु 'ड'-'ण' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'त' पर मिलती है।
- ड-ढ-ण-त : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्याक 400(भाग), 401(भाग) से बिन्दु 'थ' के पास से होकर गुजरती है और आंगिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O. 1170(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal No. S. O. 3148(E), dated the 19th November, 2015, issued under Sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd November, 2015, the Central Government gave notice of its intention to acquire mining rights in or over the lands measuring 204.67 hectares (approximately) or 505.74 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting to the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the mining rights in the lands measuring 204.67 hectares (approximately) or 505.74 acres (approximately) as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957) the Central Government hereby declares that mining rights in or over the land measuring 204.67 hectares (approximately) or 505.74 acres (approximately) as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C-1(E)III/HR/926-0216, dated the 13th February, 2016 of the area covered by this notification, may be inspected in the office of the Collector, District Chhindwara (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

Attested

JMS

SUB AREA MANAGER
LANDS SUB AREA

SCHEDULE

Expansion of Tandsi Underground Mine

Kanha Area

District Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-10/III/HR/926-02/16, dated the 13th February, 2016)

Mining Rights

Sl. No.	Name of village	Name of the Forest	Patwar Circle number	Name of the Range/Block/Compartment Number	Taluk	District	Description of land (in hectares)				Remarks
							Tenancy	Government	Forest	Total	
1	Karanjpani Dhundhi	-	07	-	Junnardeo	Chhindwara	7.840	82.81	-	90.65	Full
2	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 400	Junnardeo	Chhindwara	-	-	20.544	20.544	Part
3	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 401	Junnardeo	Chhindwara	-	-	61.794	61.794	Part
4	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 402	Junnardeo	Chhindwara	-	-	02.719	02.719	Part
5	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 410	Junnardeo	Chhindwara	-	-	16.174	16.174	Part
6	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 413	Junnardeo	Chhindwara	-	-	12.789	12.789	Part
Total :							7.840	82.81	114.020	204.670	-

Total : 204.670 hectares (approximately)

or 505.74 acres (approximately)

Plot numbers acquired in village Karanjpani Dhundi :

Tenancy : 76, 77, 86, 93, 97, 100, 102, 115, 118, 120 and 123.

Government : 26 to 75, 78 to 85, 87 to 92, 94 to 96, 98, 99, 101, 103 to 114, 116, 117, 119, 121, 122 and 124.

Compartment numbers within forest boundary : P400, P401, P402, P410 and P413.

Boundary Description :

A - B : Line starts from Point 'A' in Compartment number P401, then line passes through Compartment number P402, P410 and meets at Point 'B'.

B-C-D : Line passes nearby Point 'C' through Compartment number P410 and meets at Point 'D'.

D-E-F-

G - H : Line passes nearby Point 'E'- 'F'- 'G' along the outer boundary of plot numbers 112 (Government), 124 (Government), 121 (Government) in village Karanjpani Dhundhi and meets at Point 'H'.

H-I-J-

K-L-M : Line passes nearby Point 'I'- 'J'- 'K'- 'L' through Compartment number P413 and meets at Point 'M'.

M-N-O-P : Line passes nearby Point 'N'- 'O' through Compartment number P400 and meets at Point 'P'.

P-Q-A : Line Passes through Compartment number P400, P401 and meets at starting Point 'A'.

[F. No. 43015/15/2015- PRIW- I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

Attest
[Signature]

**SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA**

COST BENEFIT ANALYSIS

Cost benefit analysis in respect of diversion of 206.826 Ha. Forest land underground coal mining in Tandsi UG Mine, WCL.

Table- A : Cases under which a cost- benefit analysis for forest diversion are required.

S.NO.	Nature of proposal	Applicable/ not applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectares in hills.	Not applicable	
2	Proposal for defence installation purposes and oil prospecting (prospecting only).	Not applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction.	Not applicable	
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installations like micro-waves stations, auto repeater centers, TV towers etc.	Applicable	The proposed project is for diversion of 206.826 Ha. Forest Land (protected forest) for Underground coal mining at Tandsi Mine, Kanhan Area , Western Coalfields Limited, Tehsil Junnardeo , Dist. Chhindwara , Madhyapradesh, 480555

A Hester

Smf

SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

Smf

ll

Table 13 : Estimation of cost of forest diversion.

S.NO.	Parameters	Remarks.	Cost in Rs.
1	Ecosystems services losses due to proposed forest diversion.	Economic value of loss of ecosystem services due to proposed diversion of Forest NPV amount of forest land being diverted as prescribed by Central Government (MOEF&CC)	Economic Value of loss of ecosystem Services due to proposed diversion of Forest shall be Rs. 12,28,590/- Ha. (NPV rate as per ECO Value of Class III(c) forest as per Handbook Guideline of MOEF & CC, Gov dated 06/11/2022) As prescribed by Central Government (MOEF & CC) Since the project is for Underground Mining hence NPV value is considered at 5% 5% Total forest area = 206,826 ha. Environment loss = 206,826x Rs. 12,28,590 X 25 % = Rs. 6,35,26,088.80/- (Approx) The cost will be decided by Forest Dept., User agency is committed to deposit the same amount as per direction of Forest Dept.
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder.	It is Underground so no loss of animal husbandry productivity.	Nil
3	Cost of human resettlement.	no human resettlement is involved.	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, buildings, schools, dispensaries, electric lines railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No such diversion is involved.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Attested

[Handwritten signature]

TANDSI SUB AREA

3

		remarks	Cost		
5	Possession value of forest land diverted.	The project is an underground mine whole forest land will be handed to forest dept.	Nil		
6	Cost of suffering to oustees.	No rehabilitation or shifting is involved in this project	Nil		
7	Habitat Fragmentation Cost.	No fragmentation is involved	Nil		
8	Compensatory Afforestation and soil & moisture conservation cost.	not applicable	Nil		

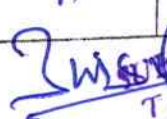
Total cost sl no 01 to 08 Rs. 6,35,26,088 80/-

Handwritten signature

Attested
[Signature]
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

Table- C - Existing guidelines for estimating benefits of forest-diversion in MCR

S.NO.	Parameters	Remarks	Benefits (in Rs.)
1	Increase in productivity attribute to the specific project.	total 3.36 MT coal expected.	33,36,000 Tes @ Rs 3396.00/Te. (WG-IV) = Rs. 1132,90,56,000/-
2	Benefits to economy due to the specific project.	various statutory levies have been considered	APPROXIMATE 15 % sale value = 1699358400
3	No. of population benefited due to specific project.		Direct = 682 Nos. Indirect = 200 Nos. Employment generated on non forest land in Afforestation programme. Local people will have income opportunity in various ancillary work & other activities.
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.		Direct = 682x Rs. 191972.82 x 120 (month) = Rs. 1571105588.80/- Indirect = 1500x Rs. 20000 x (120 month) = Rs. 3,00,00,000/- Total = Rs. 1574105588.8/-
5	Economic benefits due to Compensatory Afforestation.	Benefits from such compensatory Afforestation accruing over next 50years monetized and discounted to the present value should be included as benefits of compensator Afforestation.	This is underground mine.No need of compensatory afforestation.

Attested

 AREA MANAGER
 TANDST SUB AREA

10.

Total benefits due to diversion of forest land for non forest activity = 28769469989.00- COST BENEFIT ANALYSIS

- 1- Total benefit to the society : Rs. 28769469989/-
- 2- Total cost to the society : Rs. 63526088.80/-
- 3- Cost Benefit Ratio : Rs. 28769469989/- / Rs. 63526088.80/-

[Signature]
SITVEYOR
Towdar Mine

[Signature]
Agent
28.10.22
T S A

[Signature]
28/10/23
Area Planning officer
Kanhon Area

[Signature]
28.10.23
Area General Manager
M.C.L. Kanhon Area

[Signature]
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

No. 13016/11/2007-CA-II
Government of India
Ministry of Coal

Shastri Bhawan, New Delhi, dated 26.10.2007.

To
Chairman-cum Managing Director
Western Coalfields Ltd
Nagpur

Subject: - Approval of Mining Plan in respect of (i) Ambara Colliery (UG & OC) for grant of renewal of mining lease (ii) Mohan Colliery (Maori UG & Mohan OC Patches) for grant of renewal of mining lease (iii) Chhinda Colliery & New Sethai Colliery (OC Patches) for grant of renewal of mining lease of coal and (iv) Tandsi UG Colliery (Maori UG & Mohan OC Patches) for grant of renewal mining lease of coal of Western Coalfields Limited (WCL).

I am directed to refer to your letter No. WCL/C-1(E)/Planning/672 dated 9/10/2007 on the subject mentioned above and to convey approval of the Mining Plans in respect of (i) Ambara Colliery (UG & OC) for grant of renewal of mining lease (ii) Mohan Colliery (Maori UG & Mohan OC Patches) for grant of renewal of mining lease (iii) Chhinda Colliery & New Sethai Colliery (OC Patches) for grant of renewal of mining lease of coal and (iv) Tandsi UG Colliery (Maori UG & Mohan OC Patches) for grant of renewal mining lease of coal of Western Coalfields Limited (WCL) under Section 5 (2) (b) of the MMR Act, 1957 by the Central Government with the following conditions:

- 1) The mining company shall take all necessary precautions regarding safety of mine workings, persons deployed therein.
- 2) The approval of the Mining Plans is without prejudice to the requirement of approvals from competent/prescribed authority under the relevant rules/regulations etc.
- 3) Two copies each of the approved mining plan are enclosed herewith.

Yours faithfully,
[Signature]
28/10/07
(Alice Kujur)

Under Secretary to the Govt. of India

Mining plan

Attested

[Signature]

SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

कान्हा नागपुर कोर्ट के अधीन क्षेत्र में

Under jurisdiction of Nagpur Court Only



वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड: Western Coalfields Limited

मिनिरान्स कंपनी (A Miniransa Company)

कोयला इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी (A Subsidiary of Coal India Limited)

CIN:U10100MH1975GO1018626



कान्हा क्षेत्र

क्षेत्रीय महाप्रबंधक का कार्यालय, कान्हा क्षेत्र

Office of Area General Manager, Kanhan Area

पता: सेकोलिव, कान्हा क्षेत्र, पोस्ट: दुंगरिया, जिला:

Address: WCL, Kanhan Area, PO: Dugaria, Dist: Chhindwara, MP, PIN: 480553

छिंदवाड़ा, प.प.पिन: 480553

E-mail: agmkanhan@westerncoal.gov.in

FAX: 07160-230520, Phone: 07160-231245

संदर्भ सं: सेकोलिव/कान्हा/योजना/2023/514

दिनांक: 26-10-2023

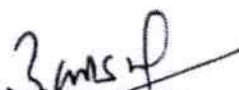
वचन पत्र

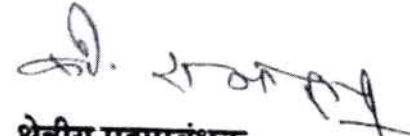
वनभंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के कक्ष क्र.पी.एफ. 400,401,409,410,413,414 एवं 422 में से 206.806 वन भूमि तानसी परियोजना भूमिगत कोयला खदान से कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को उपयोग में देने हेतु (प्रस्ताव क्रमांक -FP/MP/MIN/44238/2020) वन विभाग के समक्ष प्रकियाधीन है।

वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक: संदर्भ संख्या:-8-21/2023-FC दिनांक- 08-08-2023 के अनुसार 22 बिन्दुओं पर जानकी चाही गई है, बिन्दु क्रमांक- 17 में वर्णित बिन्दु हेतु वचन पत्र चाहा गया है,

"The State Govt., recommended the proposal subject to a study which is to be carried out by the WII, Dehradun and the State Forest Research Institute, Jabalpur to curb the noise level arises due to mining and allied activities. However, the copy of undertaking from the user agency to bear the cost of study has not been submitted. The same needs submission."

उपरोक्त कार्य के अध्ययन में जो लागत राशि वन विभाग आवेदन संस्थान को अधोरोपित करेगा। लागत राशियों का मुआवजा देने के लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।


उपक्षेत्रीय प्रबंधक,
तानसी उपक्षेत्र


क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
कान्हा क्षेत्र 26.10.23




SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA



वेस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड/ Western Coalfields Limited
मिनिरात्रा कम्पनी/ (A Miniratna Company)
कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी/(A Subsidiary of Coal India Limited)
CIN-U10100MH1975GO1018626



एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

क्षेत्रीय महाप्रबंधक का कार्यालय, कन्हान क्षेत्र
पता: वेकोलि, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट: डुंगरिया, जिला:
छिंदवाड़ा, म.प्र.पिन: 480553
Email: agmkanhan@westerncoal.gov.in

Office of Area General Manager, Kanhan Area
Address: WCL, Kanhan Area, PO: Dungaria,
Dist: Chhindwara, MP, PIN: 480553
FAX: 07160-230520, Phone: 07160-231245

संदर्भ सं: वेकोलि/कन्हान/योजना/2023/1508

दिनांक: 25-09-2023

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
तुलसी नगर, भोपाल,

विषय: छिंदवाड़ा जिले के तानसी भूमिगत खदान में प्रस्तावित 206.826 हे. वन क्षेत्र में खनन कार्य से ताम्बिया एवं सहायक नदियों पर होने वाले प्रभाव पर टिप्पड़ी के संबंध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार के वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक: 8-21/2023-FC, दिनांक 08/08/2023 विषयांतर्गत "Diversion of 206.826 ha forest land in the Forest compartment No PF-400, 401, 409, 410, 413, 414, 422 of Damua Range under West Chhindwara Forest Division for the Tandsi Under-ground Coal Mining Project by M/s Western Coalfield Limited (WCL) under Chhindwara District of Madhya Pradesh State. (Online No. FP/MP/MIN/44238/2020)- regarding."

महोदय,

आवेदक संस्थान द्वारा छिंदवाड़ा जिले के तानसी भूमिगत खदान में 206.826 हे. वन क्षेत्र में भूमिगत खनन कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु आवेदक संस्थान ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में भारत सरकार के वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक: 8-21/2023-FC, दिनांक 08/08/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग से संबंधित निम्न जानकारी पर टिप्पड़ी चाही है।

Quote

"Tambia River and its tributaries are flowing through the forest land proposed for diversion. In this regard, the comments of the Water Resource Department of the State/State Government on the effect of underground mining on ground water recharge and existing water tank and measures to protect river subsidence due to under-ground mining shall be submitted. The details of study carried out, if any in this regard shall also be submitted. "


Unquote

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA.

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय पर विभागीय टिप्पणी करने की कृपा करें।

संलग्न: पत्र क्रमांक: 8-21/2023-FC, दिनांक 08/08/2023

भवदीय


क्षेत्रीय महाप्रबंधक
कन्हान क्षेत्र
25.9.23,

प्रतिलिपि:-

1. TS TO D(T) Production & Planning, वेकोलि मुख्यालय नागपुर
2. महाप्रबंधक (पर्यावरण), वेकोलि मुख्यालय नागपुर
3. महाप्रबंधक (भू-राजस्व), वेकोलि मुख्यालय नागपुर
4. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, तानसी उपक्षेत्र
5. क्षेत्रीय योजना अधिकारी, कन्हान क्षेत्र
6. क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी, कन्हान क्षेत्र
7. नोडल अधिकारी (पर्यावरण), कन्हान क्षेत्र



SUB AREA MANAGER
TANDSI SUB AREA

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, लिंक रोड क्रमांक-2, तुलसी नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674318, 2674337, E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/व.त.अ.-1/ 9779
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 7/11/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध शाखा)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के वन कक्ष पी.एफ. 400, 401, 409, 410, 413, 414 एवं 422 के रकबा 206.826 हे. वन भूमि में तानसी कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का-वेस्टर्न, कोल फील्ड्स लि. का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/44238/2020.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/833/2022/10-11/4341 दिनांक 29.09.2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 25.03.2013 में 64-तांसी (तांडसी)-I एवं 65-तांसी (तांडसी)-II अण्डरग्राउंड कोल माइन्स के संबंध में यह लेख किया है कि इन माइन्स के अंतर्गत कोयले का खनन प्रवेश सुरंगों (incline) के माध्यम से किया जा रहा है जिसके कारण खनन गतिविधियों का भूमि सतह पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि कोयले के शेष भण्डार को खनन कर इन्हीं प्रवेश सुरंगों के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है तो इसे मान्य किया जा सकता है। इस कारण मौजूदा प्रवेश सुरंगों के माध्यम से इस क्षेत्र में अवशेष बचे कोयले के भण्डार के खनन हेतु यदि कोई अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता हो तो वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत उस भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। किन्तु भूमि सतह पर किसी भी नयी गतिविधि, जिसमें कोयला खनन हेतु नये प्रवेश सुरंगों का निर्माण भी सम्मिलित है, की अनुमति नहीं प्रदान की जाये। वन्यजीवों पर पड़ने वाले व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये इन माइन्स से निकाले जाने वाले कोयले से भरे ट्रकों का परिवहन केवल दिन के समय ही अनुमेय होगा।

भूमिगत कोयला भण्डार की समाप्ति के पश्चात खनन क्षेत्र में कोई भी अन्य गतिविधि नहीं की जावेगी, खासकर इसके ओपन कॉस्ट माइनिंग में परिवर्तन की। माइन के बंद होने के पश्चात खनन क्षेत्र में स्थित सभी मौजूदा अधोसंरचनाएं नष्ट कर दी जायेंगी और इस क्षेत्र में उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जायेगा।

66-ताम्बिया, 67-तांडसी-III तथा 68-धनवा ब्लॉकों में अब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और यह सभी क्षेत्र अच्छे वन क्षेत्र हैं। इन ब्लॉकों में कार्य करने के लिये नई

प्रवेश सुरंगों और संबंधित अधोसंरचनाओं जैसे रोड, क्रशर, कार्यालय एवं आवासीय भवन आदि के निर्माण की आवश्यकता होगी। कोयले के खनन के लिये भूमि सतह पर होने वाली इन गतिविधियों के कारण कॉरीडोर क्षेत्र से वन्यप्राणियों के आवागमन में बाधा पहुंचने की संभावना होगी। अतः इन नये ब्लॉकों में कोयला खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।


अतः यदि तांसी (तांडसी)-I एवं तांसी (तांडसी)-II अण्डरग्राउंड कोल माइन्स में अवशेष कोयला भण्डार के खनन हेतु 206.826 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है तो उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार पुनः दोहराई जाती हैं:

1. कोयले के शेष भण्डार का अण्डरग्राउंड खनन कर मौजूदा प्रवेश सुरंगों के माध्यम से ही बाहर निकाला जाये।
2. भूमि सतह पर किसी भी नयी गतिविधि, जिसमें कोयला खनन हेतु नये प्रवेश सुरंगों का निर्माण भी सम्मिलित है, की अनुमति नहीं प्रदान की जावे।
3. वन्यजीवों पर पड़ने वाले व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये इन माइन्स से निकाले जाने वाले कोयले से भरे ट्रकों का परिवहन केवल दिन के समय ही अनुमेय होगा।
4. कॉरीडोर क्षेत्र से गुजरने वाले परिवहन मार्ग के दोनों ओर प्रत्येक किलो मीटर पर वन्यप्राणियों की उपस्थिति और उनकी सुरक्षा संबंधी साइनेजेस लगाये जायें। यह साइनेज वन विभाग के साथ चर्चा कर वन विभाग द्वारा दिये गये स्पेशीफिकेशन के आधार पर तैयार कराये जायेंगे।

66-ताम्बिया, 67-तांडसी-III तथा 68-धनवा ब्लॉकों में जहां अब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, कोयला खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

चूंकि इन प्रकरणों का संबंध पेंच-सतपुड़ा वन्यप्राणी कॉरीडोर में स्थित वन भूमि से है और इस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति भी सर्वमान्य है अतः इस प्रकरण में राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की अनुशंसा एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी।

Minist
27/11/23


(असीम श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल